सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
इंदौर
बुधवार, 15 अप्रैल, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 192, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अमेरिका द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी?

संदीप राय

जंग ख़त्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फ़ेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10 बजे ईएसटी (और भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे) से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी करेंगी। हालांकि सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं होर्मुज़ स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर आने-जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही को नहीं रोकेंगी। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20 फ़ीसदी तेल और एलएनजी का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारत अपनी खपत का लगभग 90 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुज़रता है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, बीते सालों में भारत अपने पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में ख़ासी विविधता ले आया है और अब वह 41 देशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत ने कहा, 'भारत अपनी ज़रूरत का क़रीब 90 प्रतिशत तेल आयात करता है जिसमें 50 प्रतिशत होर्मुज़ से होकर आता है। अभी जो भी ख़रीद हो रही है, वो ऊंचे दामों पर हो रही है। ब्लॉकेड इस समस्या को बढ़ाएगा ही।' भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 50% से ज़्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आया था, ख़ासकर इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से।

लेकिन 2019 से 2022 के बीच भारत की मध्य पूर्व पर यह निर्भरता 60% से भी ऊपर चली गई थी। इस भारी निर्भरता को देखते हुए, क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि पीआईबी के अनुसार भारत का 70 प्रतिशत कच्चा तेल आयात अब होर्मुज़ स्ट्रेट से बाहर से आता है और एनर्जी सप्लाई सुरक्षित बनी हुई है।

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, भारत लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। हर्ष पंत के अनुसार, 'भारत अपनी ज़रूरत का 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज़ से होकर आता है।' क़तर एलएनजी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने इसका उत्पादन रोक दिया है। क़तर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है।

इन सब हालात में, भारत में कंपनियों के लिए लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की औद्योगिक आपूर्ति में 20 प्रतिशत की कटौती की पहले ही घोषणा कर दी है। हर्ष पंत का कहना है कि पहले ईरान और अब अमेरिका के ब्लॉकेड से हॉर्मुज़ से एनर्जी परिवहन का मुद्दा और जटिल हो गया है और इससे चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया पर सबसे अधिक असर पड़ने वाला है।

हालांकि जिस समय ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना होर्मुज़ की नाकाबंदी करेंगी, ये ख़बर भी आई कि 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर ईरानी टैंकर भारत की ओर रवाना हुए हैं। ऐसा बीते सात साल में पहली बार हुआ है। इस तेल का आयातक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बताया गया है। आने वाले दिनों में ईरान से कई मिलियन बैरल और तेल भारत आएगा। बीते रविवार को ईरानी झंडे वाले तीन जहाज़ होर्मुज़ स्ट्रेट को पार कर अरब सागर में पहुंचे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया का लगभग एक-तिहाई फ़र्टिलाइज़र- जैसे कि यूरिया, पोटाश, अमोनिया और फ़ॉस्फ़ेट- आमतौर पर होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर जाता है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, जंग शुरू होने के बाद से इस मार्ग से फ़र्टिलाइज़र-संबंधी उत्पादों की शिपमेंट लगभग ठप पड़ गई है। भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़र्टिलाइज़र उपभोक्ता है, और कच्चे माल के साथ ही तैयार उत्पादों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। इनका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुज़रता है। भारत हर साल लगभग 4 करोड़ टन यूरिया इस्तेमाल करता है, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। आपूर्ति बाधित होने से किसानों के बुवाई के फ़ैसले प्रभावित हो सकते हैं। कई विश्लेषकों की तरह ही हर्ष पंत का कहना है कि अगर होर्मुज़ खुल भी जाता है तो जंग से पहले वाली स्थिति में लौटने में छह महीने से एक साल तक लग जाएंगे।एनर्जी सेक्टर को हुए नुक़सान को ठीक करने में, होर्मुज़ में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उन्हें हटाने में और परिवहन बीमा में जो भारी बढ़ोतरी हुई है, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव बना रहेगा।

अमेरिका भारत में निर्मित जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है और साल 2024 में भारत ने 9 अरब डॉलर के फ़ार्मा उत्पाद का अमेरिका में निर्यात किया था। हर्ष पंत का कहना है कि जंग की अनिश्चितता ने वैश्विक फ़ार्मा सप्लाई चेन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, भारत इससे अछूता नहीं रहेगा। होर्मुज़ पूरी तरह से शटडाउन नहीं भी है तो भी, परिवहन की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा आपूर्ति का समय भी खिंच रहा है। इससे महंगाई बढ़ेगी।' एनर्जी सप्लाई चेन में बाधा की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर की आशंकाएं गहराने लगी हैं।

हर्ष पंत के अनुसार, आयात महंगा होने से राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा और इसका असर व्यापार संतुलन पर पड़ेगा। दूसरी तरफ़ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। आयात महंगा होगा। ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस जंग से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और ऐसा होता है तो भारत को खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस (भारतीय जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं) पर भी असर पड़ेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि दुनिया के बाक़ी देश ट्रंप पर जंग ख़त्म करने का दबाव डालें। अब यही काम अमेरिका करना चाहता है। होर्मुज़ की नाकाबंदी करके अमेरिका चीन, भारत, जापान समेत उन देशों पर दबाव डालना चाहता है जिनकी इस समुद्री रास्ते पर निर्भरता अधिक है।'

शिपिंग विशेषज्ञ वेस्पुच्ची मरीन के सीईओ लार्स जेनसेन ने कहा कि होर्मुज़ बंद करने की ट्रंप की धमकी का असर बहुत सीमित संख्या में जहाज़ों पर पड़ेगा। ज़्यादातर शिपिंग कंपनियां इंतज़ार करेंगी कि क्या कोई अस्थायी शांति समझौता होता है और क्या वह टिकाऊ रहता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

पाटलिपुत्र के नए 'सम्राट' का ऐलान

● बिहार में अब बीजेपी राज, पहले सीएम होंगे सम्राट चौधरी ● चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता,आज 11 बजे शपथ

पटना (एजेंसी)। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। कल 15 अप्रैल को लोकभवन में शपथग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आज नीतिश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा- 'अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा।

संगठन और अनुभव बना ताकत

सम्राट चौधरी लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनकी भूमिका अहम रही है। सरकार में मंत्री और उपमुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव हासिल किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता को पार्टी ने प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। कल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। राजभवन में इसकी तैयारियां शुरू होने की चर्चा है। नई कैबिनेट को लेकर भी मंथन जारी है। कौन-कौन मंत्री बनेगा, इस पर विचार किया जा रहा है। संतुलन साधने की कोशिश पार्टी स्तर पर चल रही है। औपचारिक घोषणा का इंतजार भी खत्म हो गया है।

कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की खबर से कार्यकर्ताओं में खुशी है। पार्टी कार्यालयों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का दौर जारी है। इसे भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर दिखने की उम्मीद है। अब सभी की नजर नई सरकार की कार्यशैली पर टिकी है। विकास और सुशासन को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। नई सरकार के एजेंडे को लेकर चर्चा तेज है। राज्य में तेजी से फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं। बिहार की राजनीति में नया दौर शुरू होता दिख रहा है।

शरद की सुबह

तुम रहते हो...
आखिरी साँस तुमने ली
जिन्दगी मेरी रुक गई
मृत्यु-शैय्या पर लिटाया गया तुम्हें
जलती मैं रही
तुम रहते हो हमारे आसपास
आसमान के धुँधलके के समान
फीके पत्तों के रंग में
मेरी रुक-रुककर बजती
आवाज़ के साथ
हमारे प्रेमालापों के बीच
पसरते हो धीमे से
बढ़ते बच्चों के फीते बाँधते
गुनगुनाते उनके जवान होने का गीत
हौले से थपथपाते
मेरी पीठ
मैं तुम्हें यूँ ही
मरने नहीं दूँगी।

– प्रज्ञा रावत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भीम जन्मभूमि (महू) पहुंचकर बाबा साहेब को अर्पित की पुष्पांजलि

संविधान निर्माता होने के साथ नए भारत के निर्माता भी हैं बाबा साहेब

भोपाल/महू (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि पर उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहेब एक ऐसे युग दृष्टा थे, जिन्होंने एक हजार साल की गुलामी की कठिनाइयों को दूर करने और समाज के अंदर समानता के भाव को विकसित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहेब के योगदान से हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हमें उनके बनाए संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। इससे श्रेष्ठ संविधान और कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा महिला समानता और सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों और उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने बहनों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाने, तलाक के समय मुआवजा और मातृत्व अवकाश दिलाने के लिए सराहनीय कार्य किया। उन्होंने हमें माताओं-बहनों के लिए 'समान काम-समान वेतन' का दूरदृष्टिपूर्ण विचार दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को इंदौर के डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में डॉ. अम्बेडकर की जन्मभूमि परिसर में आयोजित जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे।

लोकसभा और विधानसभा में सुनिश्चित होगा 33 प्रतिशत आरक्षण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा साहेब महिला सशक्तिकरण के साहसी और प्रबल समर्थक थे। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। न्यूनतम मजदूरी, कंपनी लॉ और महिला श्रमिकों को अधिकार हमें बाबा साहेब की ही देन है। केन्द्र सरकार संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों पर चलते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आने वाले दिनों में लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पूर्ण रूप से लागू करने पर चर्चा होगी, इससे माताओं-बहनों को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने अनुयायियों संग सहभोज कर दिया समरसता का संदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत रत्न डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जन्मस्थली स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए अनुयायियों के साथ सहभोज कर सामाजिक समरसता का प्रेरक संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर देशभर से पधारे श्रद्धालुओं के साथ पंक्तिबद्ध बैठकर सह भोज किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हमें समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंबेडकर जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज में समरसता और एकता को सुदृढ़ करने का अवसर है। इस प्रकार का सहभोज समाज में भेदभाव मिटाने और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। हमें बाबा साहब अम्बेड़कर के सामाजिक समरसता के संदेश को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

लता -आशा की याद में बनेगा अस्पताल

मुंबई (एजेंसी)। सिंगर लता मंगेशकर और आशा भोसले की याद में पुणे में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। दोनों सिंगर्स के भाई और म्यूजिक डायरेक्टर हृदयनाथ मंगेशकर ने सोमवार को यह जानकारी दी। हृदयनाथ मंगेशकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुणे में उनकी मां और लता मंगेशकर ने गरीबों की सेवा के लिए अस्पताल बनाने का सपना देखा था। उन्होंने बताया कि करीब 25 साल पहले परिवार और डॉक्टरों ने इस अस्पताल को बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय यह पूरा नहीं हो सका। हृदयनाथ ने कहा कि बाद में परिवार ने फैसला लिया था कि अस्पताल लता मंगेशकर के नाम पर बनाया जाएगा और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं।

अमेरिका बातचीत नहीं, शर्तें थोपना चाहता है

ईरान बोला-उनकी नीयत पर शक,पीस डील पर मीटिंग संभव

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। ईरान ने अमेरिका पर बातचीत के बजाय शर्तें थोपने का आरोप लगाया है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि अमेरिका की मंशा शुरू से ही संदिग्ध रही है। अयोध्या में दिए बयान में इलाही ने कहा कि अमेरिका बातचीत नहीं करना चाहता, बल्कि दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वहां नाकाबंदी कर रहा है। इलाही ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और शांति का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका का रवैया इसके विपरीत है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर गुरुवार तक दूसरी बैठक होने की संभावना है। दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश में हैं।

मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जिनपिंग का चार सूत्रीय प्रस्ताव- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव उन्होंने मंगलवार, 14 अप्रैल को बीजिंग में यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान दिया। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी जिनपिंग ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का पालन जरूरी है।

ईरान बोला- युद्ध में 25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ

ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसे करीब 270 अरब डॉलर (25 लाख करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ है। ईरान सरकार के प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने बताया कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ भी सकता है। फातेमेह मोहाजेरानी ने बताया कि ईरान की तरफ से बातचीत करने वाली टीम इस मुद्दे को भी उठा रही है। खासकर इस्लामाबाद में हुई बातचीत में युद्ध के नुकसान की भरपाई की मांग की गई थी। ईरान ने साफ किया है कि वह शांति के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं।

मोदी देशद्रोही, मुझसे तो नजर मिलाकर बात नहीं कर पाते

● बंगाल में बोले राहुल गांधी,ट्रेड डील को बताया बेहद खतरनाक

कोलकाता (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल विधानसभा चुनाव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और उन्हें 'देशद्रोही' तक बता डाला। राहुल गांधी ने कहा कि मालदा की रैली में कहा कि पीएम मोदी देश भक्त नहीं हैं बल्कि वह देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील देश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसके चलते देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट भी पैदा होगा। उन्होंने इस दौरान एसआईआर की भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर में बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए हैं और ऐसा करना असंवैधानिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटे हैं। उन्हें कांग्रेस की सरकार आने पर वापस जोड़ा जाएगा।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 15 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

आज जारी होगा एमपी शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट

● टॉपर्स को कैश प्राइज और लैपटॉप देगी सरकार

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2026, बुधवार को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से भोपाल स्थित बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। रिजल्ट की ऑफिशियल डेट बोर्ड ने सोमवार (13 अप्रैल 2026) को ही जारी कर दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी रिजल्ट की तारीख की पुष्टि कर दी थी। इस साल एमपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

टॉपर्स को किया जाएगा सम्मानित– मध्य प्रदेश माध्यमिक

शिक्षा मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टॉपर्स का नाम भी जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद जो टॉपर्स होंगे उन्हें राज्य सरकार की ओर से कैश प्राइज और अन्य ईनाम के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य में टॉप पोजिशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही प्राइज मनी और ईनाम भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की कैश राशि और लैपटॉप दिया जाएगा। मुख्य पुरस्कारों में मेधावी छात्राओं को स्कूटी और ग्रामीण क्षेत्रों के टॉपर्स को साइकिल दी जा सकती है। 12वीं के जिन स्टूडेंट्स ने 75 परसेंट या उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे उन्हें कैश प्राइज मिलेगा। पिछले साल टॉपर्स को यही सब दिया गया था। 2025 में एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया था।

महंगाई के लिए रहिए तैयार, चुनाव बाद पड़ेगी भारी मार

● पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए तक हो सकता है महंगा ● बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 और डीजल 35 प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्कायरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं। इससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं।

हर दिन 1,600 करोड़ का नुकसान झेल रहीं कंपनियां- कच्चा तेल महंगा होने से कंपनियों को प्रति लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले महीने के पीक पर ये तीनों कंपनियां हर दिन करीब 2,400 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही थीं। एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती के बाद यह घाटा घटकर 1,600 करोड़ रुपए रह गया है। हर 10 डॉलर के उछाल से नुकसान करीब 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है।

● **अमेरिका सहित कई देशों ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम**- अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमतें अगस्त 2022 के बाद पहली बार 4 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई हैं। वहीं पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका सहित कई पड़ोसी देशों ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा किया है।

भारत 88 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से 45 फीसदी मिडिल ईस्ट और 35 फीसदी रूस से आता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें न केवल तेल कंपनियों, बल्कि देश के चालू खाता घाटे के लिए भी खतरा हैं। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही में यह घाटा बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। सरकारी राजस्व में तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का योगदान लगातार कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2017 में यह 22 था, जो अब घटकर सिर्फ 8 फीसदी रह गया है। अगर सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी हटा भी दे, तो भी मौजूदा कीमतों पर घाटा खत्म नहीं होगा।

'बजट क्रेस्ट 2026' के द्वितीय दिवस का सफल आयोजन

'मेरा युवा भारत' का मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करता: मंडाविया

केंद्रीय खेल मंत्री एवं मप्र के मंत्री विश्वास सारंग व विशेषज्ञों ने युवाओं के साथ किया संवाद

भोपाल। मध्य प्रदेश में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित 'मेरा युवा भारत' कार्यक्रम के तहत आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर 'बजट क्रेस्ट 2026' का सफल एवं प्रभावी आयोजन एलएनसीटी कॉलेज, भोपाल में संपन्न हुआ। इस दिन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश की आर्थिक नीतियों, बजट प्रक्रिया एवं समावेशी विकास के विभिन्न आयामों से अवगत कराना रहा।

शुभारंभ मंत्री विश्वास सारंग ने दीप प्रज्वलन कर किया – कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे के साथ-साथ श्री किशन सिंह सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष, भोपाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय अतिथियों का स्वागत राज्य निदेशक श्रीमती तारा पारगी एवं राज्य निदेशक श्री मंगलराम जाखड़ द्वारा किया गया।

अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में मंत्री श्री सारंग ने युवाओं को देश के महान महापुरुषों के उदाहरण देते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और यदि युवा सही दिशा, दृष्टि एवं संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तो देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद रहा। अपने संबोधन में उन्होंने 'मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए युवाओं को इस मंच से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म युवाओं को कौशल विकास, स्वयंसेवा, नेतृत्व एवं नवाचार के अवसर प्रदान करता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयगत सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।

विकसित कृषि सत्र

इस सत्र में कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक कृषि, तकनीकी नवाचार एवं किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।एच. आर. प्रभाकर, सहायक निदेशक, कृषि विभाग। खुदीराम सनोदिया, एसडीओ, कृषि विभाग डॉ. अक्षय जैन, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एलएनसीटी कॉलेज।वक्ताओं ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग, सतत कृषि पद्धतियों, नवाचार एवं युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।

ह्यूमन कैपिटल

इस सत्र में मानव संसाधन विकास, कौशल उन्नयन एवं नीति-निर्माण के महत्व पर चर्चा की गई। मनोज कुमार जैन, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रमुख, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस श्रीमती रोमा बाजपेई, निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क वक्ताओं ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों एवं भविष्य की अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी की भूमिका पर गहन विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बजट प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं एवं नीति-निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही, युवाओं को यह भी बताया गया कि वे किस प्रकार 'मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। समग्र रूप से 'बजट क्रेस्ट 2026' का द्वितीय दिवस ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं सहभागितापूर्ण रहा, जिसने युवाओं को न केवल आर्थिक एवं नीतिगत समझ प्रदान की, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित किया। अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को माय भारत बजट क्रेस्ट संबंधित संदेश सुनाया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्री ओम तिवारी व श्री तरुण विश्वकर्मा द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन उपनिदेशक श्रीमती मोनिका चौधरी द्वारा किया गया। यह आयोजन युवाओं को सशक्त बनाने, उनके विचारों को मंच प्रदान करने एवं उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सफल रहा।

आई पैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार

● बंगाल चुनाव से 10 दिन पहले ईडी की कार्रवाई

टीएमसी ने कहा- इससे डर का माहौल बनता है

नई दिल्ली/कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आई पैक के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार शाम दिल्ली में पकड़ा गया। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले हुई यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाती है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और ईडी जैसी एजेंसियों की चुनाव जैसे संवेदनशील

'सबका किनारा', होर्मुज स्ट्रेट में अकेला पड़ गया अमेरिका

तेल का दाम बढ़ाकर सहयोगियों को सजा देना चाहते हैं ट्रंप

वॉशिंगटन/तेहरान (एजेंसी)। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का मकसद ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकना है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो जहाज जो ईरान को टोल चुका रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए चाहे वो किसी भी देश के हैं। ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के देश आएं और ईरान से झगड़ा करें। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया है। इसके बजाय अपने ऊर्जा कार्गो को सुरक्षित करने के लिए कई देश स्वतंत्र रूप से कदम उठा रहे हैं। जैसे भारत और चीन जैसे देश सीधे ईरानी लीडरशिप से बात कर रहे हैं। लेकिन इस नाकाबंदी के जरिए ट्रंप शायद कई अन्य देशों को भी मध्य-पूर्व संकट में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं।

पाकिस्तान के आतंक को उजागर करेगा भारत

● पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर वाशिंगटन में लगेगी प्रदर्शनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इसमें 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की कोशिश कर पाकिस्तान भले ही दुनिया को मध्यस्थ देश के तौर पर खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत उसकी सच्चाई उजागर कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर वाशिंगटन में भारतीय दूतावास 'आतंकवाद की इंसानी कीमत' थीम पर एक प्रदर्शनी लगाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह प्रदर्शनी अगले हफ्ते शुरू होगी और कैपिटल हिल के पास एक पब्लिक जगह पर होने की संभावना है। हालांकि प्रदर्शनी के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई हैं। लेकिन पता चला है कि यह प्रदर्शनी जान गंवाने वाले 26 लोगों पर फोकस करेगी।

दिल्ली से देहरादून का सफर अब मात्र ढाई घंटे में

● पीएम मोदी ने किया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ● मोदी ने कहा-2029 के चुनावों में बेटियों को उनका हक देंगे

देहरादून (एजेंसी)। पीएम मोदी ने मंगलवार को देहरादून में कहा, '4 दशकों से महिला-बेटियां अपने हक का इंतजार कर रही है। अब वह समय आ गया है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनावों में उनका हक देकर रहेंगे। इसके लिए हम संसद में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं।' पीएम ने कहा, कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थीं। आज डबल इंजन सरकार के प्रयास से सड़क गांव तक पहुंच रही है।

महिला आरक्षण पर पीएम ने रखी अपनी बात

4 दशक बाद संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। 33 फीसदी आरक्षण लागू करने वाले इस कानून को बनाने के लिए सभी दलों ने समर्थन दिया। अब इसे लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। 2029 से ही यह लागू हो जाना चाहिए। यह देश की भावना है हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में चर्चा होनी है। इसे सभी दल सर्व सम्मति से आगे बढ़ाएं। इसलिए मैंने आज देश की नारी शक्ति के नाम आज सभी बहनों के लिए एक पत्र लिखा है।

टूरिज्म बना कमाई का सबसे बड़ा जरिया

पीएम ने कहा कि टूरिज्म बढ़ने से हर वर्ग को कमाई का मौका मिलता है। होटल, टैक्सी, दुकानदार सभी को लाभ होता है। उत्तराखंड अब विंटर टूरिज्म और स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बन रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास के गेटवे हैं। इससे समय और खर्च दोनों कम होंगे। रोजगार बढ़ेगा और किसानों की उपज तेजी से बाजार तक पहुंचेगी, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

भारत में बढ़ सकते हैं 25 लाख गरीब, मुश्किल होगा इलाज

ईरान युद्ध के बीच यूएन की डराने वाली रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर पूरी दुनिया की ही अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में धकेल दिए जाने का खतरा है और देश के मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पश्चिम एशिया में सैन्य वृद्धि-एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर प्रभाव शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा कि यह संघर्ष एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास के दबाव को बढ़ा रहा है। इसमें कहा गया कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से घरेलू क्रय शक्ति घट रही है, खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, सरकारी बजट पर दबाव पड़ रहा है और आजीविका कमजोर हो रही है। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 88 लाख लोग गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं और इस सैन्य तनाव से एशिया-प्रशांत क्षेत्र को 299 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। भारत में गरीबी से प्रभावित लोगों की संख्या 25 लाख तक होगी।

गरीबी दर में भी हो सकती है बढ़ोतरी

इसमें कहा गया कि सबसे गंभीर परिदृश्य में भारत की गरीबी दर 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 24.2 प्रतिशत हो सकती है जिससे अतिरिक्त 24,64,698 लोग गरीबी में चले जाएंगे। संकट के बाद देश में गरीबी में रहने वालों की संख्या 35.40 करोड़ तक पहुंच सकती है जो पहले 35.15 करोड़ थी। रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव का भी आंकलन किया गया है। इसमें कहा गया कि भारत में एचडीआई प्रगति में लगभग 0.03 से 0.12 वर्ष तक की गिरावट हो सकती है। इसके बाद नेपाल (0.02–0.09 वर्ष) और वियतनाम (0.02–0.07 वर्ष) का स्थान है जबकि चीन पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम (0.01–0.05 वर्ष) रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी 90 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और कच्चे तेल का 40 प्रतिशत से अधिक तथा एलपीजी का 90 प्रतिशत आयात पश्चिम एशिया से करता है। इसके अलावा, उर्वरक आयात का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है। संघर्ष के कारण ऊर्जा विकल्पों पर भी असर पड़ा है। एलएनजी कीमतें बढ़ने से भारत समेत कई देशों ने कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता बढ़ाई है। व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला पर असर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 में से 25 देशों में मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी जैसी समस्याएं देखी गई हैं।

इलाज करवाना भी होगा मुश्किल

आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, इस्पात आधारित उद्योग और रत्न-हीरा क्षेत्र की छोटी कंपनियों को उच्च लागत, आपूर्ति की कमी और ऑर्डर में देरी या रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों का असर रोजगार, काम के घंटे और व्यवसाय की निरंतरता पर पड़ सकता है विशेषकर असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों पर। भारत में चिकित्सकीय उपकरणों से जुड़े माल की लागत भी होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है, जबकि दवाओं के थोक दाम पहले ही 10–15 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

नोएडा में थमा नहीं टकराव दूसरे दिन भी भारी बवाल

15 कंपनियों की फोर्स, 26 पुलिस अफसर भेजे

गौतमबुद्धनगर (एजेंसी)। नोएडा, यानी गौतमबुद्ध नगर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी मंगलवार को भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। भीड़ ने 2-3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात पर काबू पा लिया। प्रदर्शनकारियों को वहां से

खदेड़ दिया। फिलहाल, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान इंडस्ट्रियल इलाकों में सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, पीएसी और रैफ की 15 कंपनियां, 26 अफसर (8 एडिशनल एसपी और 18 डीएसपी) नोएडा भेजे गए हैं। आज ज्यादातर कंपनियां बंद हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण लखनऊ के कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे। कहा- क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई भी उपद्रवियों से कराई जाएगी। वहीं, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा- अब तक 300 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं।

भोपाल गैसकांड का कचरा जलाने वाली कंपनी में 3 धमाके

पीथमपुर में एक किमी दूर तक आवाज गूंजी; झटके से घरों का सामान गिरने लगा

पीथमपुर (नप्र)। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-2 में रामकी एनवायरो कंपनी में मंगलवार को तीन धमाके हुए। धमाकों की गूंज लगभग एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई।

विस्फोटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कंपनी के निकटवर्ती तारपुरा और बजरंगपुरा गांवों में लोगों ने झटके महसूस किए। ग्रामीणों ने बताया कि धमाकों के कारण उनके घरों में रखे बर्तन और टेलीविजन तक स्टैंड से नीचे गिर गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

सीएसपी बोले- धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा

सीएसपी रवि सोनेर ने बताया कि हम घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है

और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रामकी एनवायरो में ब्लास्ट मामले में थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहीर ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले की जांच जारी है। कंपनी प्रबंधन की तरफ से भी किसी प्रकार की जनहानि से इंकार किया गया है।

कंपनी ने भोपाल गैस कांड का जलाया था कचरा

रामकी एनवायरो कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले साल यह कंपनी भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे को जलाने के कारण देशभर में चर्चा का विषय बनी थी। कचरा प्रबंधन और निपटान का कार्य करने वाली इस कंपनी में हुए इन धमाकों ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम कंपनी के अंदर धमाके के वास्तविक कारणों की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में अभी तक कंपनी का कोई पक्ष सामने नहीं आया है।

40 लाख के लिए बुजुर्ग दंपत्ति को रातभर बंधक बनाया

बेटे की उधारी पर धमकी दी- बिहार ले जाकर किडनी निकलवा देंगे, तीन आरोपी गिरफ्तार

इंदौर (नप्र)। इंदौर में एक बेटे की उधारी की सजा उसके बुजुर्ग माता-पिता को भुगतना पड़ी। तीन बदमाशों ने 63 वर्षीय बुजुर्ग दंपती को उनके ही घर में रातभर बंधक बनाकर रखा और मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकियां दीं। घटना रविवार को हीरा नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।

करोड़ों की लेनदारी, 20 दिन से बेटा लापता

टीआई सुशील पटेल के मुताबिक, मारुति नगर निवासी रमेश जोशी (रिटायर्ड कर्मी, वर्तमान सिक्योरिटी गार्ड) का बेटा अंकित जोशी करोड़ों रुपए की लेनदारी के बाद 20 दिनों से लापता है। रविवार को अंकित से 40 लाख रुपए वसूलने के लिए अभिषेक, अंकित और गुलशन नाम के तीन युवक बुजुर्ग के घर पहुंचे।

घर में जमाया डेरा, रातभर करते रहे निगरानी

आरोपियों ने बुजुर्ग दंपती को बंधक बना लिया। उनके फोन बंद कर दिए। उन्होंने धमकाया कि अगर अंकित नहीं मिला तो तुम दोनों को जबरन बिहार ले जाएंगे। हद तो तब हो गई, जब आरोपी रातभर घर में ही डेरा जमाकर बैठ गए और बुजुर्ग दंपती की निगरानी करते रहे।

बुजुर्ग की सूझ-बूझ : बदमाशों को ऐसे दिया चकमा

सोमवार सुबह रमेश जोशी ने आरोपियों से ड्यूटी जाने की मिन्नत की। आरोपियों ने इस शर्त पर इजाजत दी कि गुलशन उनके साथ रहेगा। दिनभर पहरेदारी के बाद रात में मेघदूत गार्डन के पास रमेश जोशी ने मौका पाकर गुलशन को चकमा दिया और सीधे हीरा नगर थाने जा पहुंचे।

पुलिस का एक्शन : महिला को कराया मुक्त

बुजुर्ग की आपबीती सुनते ही टीआई ने तुरंत टीम रवाना की। पुलिस ने घर पर दबिश देकर बुजुर्ग महिला को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

72 फीट के पीतल पट्ट पर 193 देशों के प्रतीक चिन्ह बनाए

अंबेडकर जयंती पर किया जारी, 1 दिन में हुआ तैयार

इंदौर (नप्र)। महू में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर 72 फीट लंबे पीतल पट्ट का अनावरण किया गया। इस पट्ट पर दुनिया के 193 देशों के प्रतीक चिन्ह उकेरे गए हैं। इसे लोकेश मंगल ने तैयार कराया। उन्होंने बताया कि यह काम 80 एडवोकेट्स की मदद से पूरा किया गया। इस पहल के पीछे थावरचंद गेहलोत की प्रेरणा रही।

3 घंटे 10 मिनट में हुई कटिंग- यह पीतल पट्ट 72 फीट लंबा है, जबकि इसका वजन करीब 1 किलो बताया गया है। खास बात यह है कि इसे फोल्ड कर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।पीतल पट्ट की कटिंग रविवार को की गई, जिसमें 3 घंटे 10 मिनट का समय लगा। इसके बाद सोमवार को इसकी प्रिंटिंग कर 193 देशों के प्रतीक चिन्ह इसमें उकेरे गए।

विश्व शांति के संदेश के साथ पहल- लोकेश मंगल के अनुसार, यह कार्य 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और विश्व शांति के संदेश के साथ किया गया है। उनका दावा है कि यह अपनी तरह का पहला पीतल पट्ट है, जिस पर 193 देशों के प्रतीक चिन्ह एक साथ उकेरे गए हैं।

आज सात फेरों के साथ गूंजेगा वंदे मातरम्

सामूहिक विवाह में 25 जोड़े लेंगे स्वच्छता और राष्ट्र रक्षा के 9 खास वचन

इंदौर (नप्र)। इंदौर के गांधी हॉल में 15 अप्रैल को सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में 25 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह सूत्र में बंधेंगे। खास बात यह कि कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़े, बाराती और घराती सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन करेंगे।

सात फेरों के साथ नवदंपतियों को दिलाए जाएंगे नौ खास वचन- इस बार समारोह की खास बात यह रहेगी कि पारंपरिक सात फेरों के साथ नवदंपतियों को नौ विशेष वचन भी दिलाए जाएंगे। इन वचनों में इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाए रखने, राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प शामिल होगा।

इंदौर में परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रभावना का अनोखा संगम- आयोजक विधाययक गोलू शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विवाह में शामिल होने वाले सभी जोड़ों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास है। वैदिक परंपराओं के साथ संपन्न होने वाला यह सामूहिक विवाह सम्मेलन इंदौर में परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रभावना का अनोखा संगम प्रस्तुत करेगा।

कॉपी-किताब की मोनोपोली पर सख्ती, अब तक 5 केस दर्ज

एक ही दुकान से खरीदारी का दबाव नहीं चलेगा; प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इंदौर (नप्र)। इंदौर में कॉपी-किताब की कथित मोनोपोली को लेकर जिला प्रशासन सख्त रुख में है। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी अभिभावक पर एक ही दुकान से कॉपी-किताब खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

शिकायतों के बाद स्कूल और दुकानदारों पर दर्ज हुए पांच केस- इसी बीच अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर अलग-अलग थानों में अब तक 5 केस स्कूल संचालकों और स्टेशनरी व्यवसायियों के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि कहीं भी अनिवार्य खरीदारी का दबाव बनाया गया, तो संबंधित संस्थान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जबरन वसूली पर कार्रवाई और हेल्पलाइन जारी- कलेक्टर शिवम वर्मा ने हाल ही में इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर (0731-2431117) भी जारी किया गया है। मामलों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

पाटनीपुरा में आधी रात दुकान में आग

शार्ट शर्किट के चलते हुआ हादसा

इंदौर (नप्र)। पाटनीपुरा इलाके में सोमवार देर रात पूजा सामग्री की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास की दुकानों को भी एहतियातन खाली कराया गया।

फायर ब्रिगेड के मुताबिक रात करीब 1:40 बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर दमकल की दो गाड़ियां भेजी गईं। आग बुझाने के लिए करीब 17 हजार लीटर से ज्यादा पानी का उपयोग किया गया। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की।

पुलिस के मुताबिक आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई

है, हालांकि लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

भाई ने कहा, शॉर्ट सर्किट से आग लगी- दुकान मालिक सुधीर के भाई दीपक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। यहां देर रात से फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था।

शटर बंद होने से अंदर भर गया धुआं

आग विनायक पूजा पाठ सामग्री की दुकान में लगी थी। शटर बंद होने के कारण अंदर धुआं भर गया था। फायर टीम ने शटर तोड़कर अंदर पानी डाला और आग पर काबू पाया।

सूचना मिलते ही एमआईजी टीआई सीबी सिंह मौके पर पहुंचे। दुकान सुधीर अग्रवाल की बताई जा रही है। पास की अन्य पूजा सामग्री दुकानों को तुरंत खाली कराया गया।

गोलीकांड में एक आरोपी और पिस्टल की तलाश

बैंक में काम करने वाला आरोपी बोला- पहले से रखी हुई थी देसी पिस्टल

इंदौर (नप्र)। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रविवार रात में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस दो आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। मामले में पुलिस को एक और आरोपी के साथ देसी पिस्टल की तलाश है। इसके लिए टीमें लगी हुई है और जानकारी निकाल रही है।

दरअसल, रविवार रात को दो दोस्त झगड़ा सुलझाने के लिए मिले और उनके बीच फिर से झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में दोनों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया है। एक युवक ने चाकू से तो दूसरे ने देसी पिस्टल से दो से तीन फायर कर दिए थे।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और दोनों को पकड़ लिया था। इस मामले में दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

चाय चौकी कैफे में हुई घटना- लसूड़िया टीआई तारेश सोनी ने बताया कि घटना रविवार रात स्कीम नंबर 78 स्थित चाय चौकी कैफे की है। ऋषभ पिता

रघुवीर सिंह राजपूत की शिकायत पर आर्यन पटेल और निखिल उर्फ हैनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं, आर्यन पिता राजेंद्र पटेल की शिकायत पर ऋषभ सिंह राजपूत के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

घटना के बाद पुलिस ने ऋषभ और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आर्यन का साथी निखिल पिस्टल लेकर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को किसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ था। विवाद सुलझाने के लिए वे चाय चौकी कैफे पर मिले, लेकिन यहां भी उनके बीच फिर से विवाद हो गया।

झगड़े के दौरान गाली-गलौज हुई और स्टूल-कुर्सियां तक फेंकी गईं। इसके बाद आर्यन ने चाकू निकालकर ऋषभ के पैर में हमला कर दिया। वहीं, ऋषभ ने अपनी एक्टिवा से देसी पिस्टल निकालकर आर्यन पर दो से तीन फायर किए, हालांकि आर्यन बाल-बाल बच गया।

हंगामा बढ़ने पर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, जबकि अफरा-तफरी के दौरान आर्यन का साथी निखिल देसी पिस्टल लेकर फरार हो गया।

पुलिस पूछताछ में कहा- पहले से रखी थी पिस्टल

टीआई तारेश सोनी ने बताया कि आर्यन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जबकि ऋषभ एक बैंक के लोन विभाग में कार्यरत है। ऋषभ से पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास देसी पिस्टल पहले से ही रखी हुई थी। हालांकि, यह पिस्टल उसके पास कहां से आई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।इस मामले में निखिल की तलाश जारी है। वह घटना स्थल से देसी पिस्टल लेकर फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी हैं। साथ ही, उसके संभावित ठिकानों पर भी तलाश की जा रही है।

गार्डन में युवती से छेड़छाड़

मेघदूत गार्डन में शादी के लिए बुलाकर सेल्फी के बहाने छेड़छाड़, आरोपी पर एफआईआर

इंदौर (नप्र)। इंदौर के मेघदूत गार्डन में 18 साल की युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी कार्तिक चौधरी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि वह अपनी बुआ के साथ गार्डन गई थी। यहां कमल चौधरी ने शादी के लिए एक लड़का दिखाने की बात कही और कार्तिक का नंबर दिया। कार्तिक ने मिलने के लिए बुलाया। बुआ ने दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ा, इसी दौरान आरोपी ने अश्लील बातें कीं और गलत तरीके से छूने लगा।

सेल्फी लेने के बहाने किया टच- पीड़िता के अनुसार आरोपी ने कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी लेने की कोशिश की। विरोध करने पर वह तुरंत वहां से

बुआ के साथ लौट आई। बाद में मां को पूरी घटना बताने के बाद सोमवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई।

लिफ्ट में सामान रखने पर विवाद, मां-बेटी से मारपीट

एक अन्य मामले में राजेंद्र नगर इलाके में लिफ्ट में सामान रखने को लेकर विवाद के बाद मां-बेटी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक वह लिफ्ट से खाद्य सामग्री ले जा रही थी। इसी दौरान चौकीदार की पत्नी शीला पंवार ने आपत्ति जताई और अपशब्द कहे। वीडियो बनाने पर शीला का भाई रितेश राठौर मौके पर पहुंचा और मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इसके बाद मारपीट और झूमाझटकी की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रितेश ने मां के पेट में लात मारी और गुंडों से उठवाने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में शीला पंवार और रितेश राठौर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

केयरटेकर ने बुजुर्ग को नशा देकर लूटा

लाखों के जेवर लेकर भागा, बुजुर्ग के प्लॉट पर झोपड़ी बनाकर कब्जा किया, 2 पर केस

इंदौर (नप्र)। इंदौर के गुमाश्ता नगर में 75 वर्षीय बुजुर्ग को नशा देकर लूट का मामला सामने आया है। केयरटेकर बनकर आया युवक सोने की चेन, ब्रेसलेट समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हो गया।

घटना द्वारकापुरी इलाके की है। बुजुर्ग ओमप्रकाश मूंगड चलने-फिरने में असमर्थ हैं। उनकी देखरेख करने वाला राजगढ़ निवासी दिलीप सिंह छुट्टी पर था, इसलिए परिवार ने एजेंसी संचालक उमराव सिंह के माध्यम से फिरोजाबाद निवासी यश को 10 दिन के लिए बुलाया था।

रविवार को आरोपी ने योजना बनाकर बुजुर्ग को नशा दिया। उनके सोने के बाद सोने की चेन, ब्रेसलेट और अन्य जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस को घटनास्थल से नशे की पुड़िया और खाने-पीने का सामान मिला है, जिसे जब्त किया गया है। आरोपी की लोकेशन पहले देवास और फिर राजस्थान में ट्रेस हुई है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने एजेंसी संचालक उमराव सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

कब्जा हटाने के बदले मांगे 6 लाख

जब प्लॉट मालिक ने विरोध किया, तो आरोपियों ने कब्जा हटाने के बदले 6 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस पूछताछ में आरोपी जमीन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। उन्होंने प्लॉट को सुरेश कानूनगो से लेने की बात कही, लेकिन जांच में सामने आया कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। जांच में पुलिस ने पाया कि दोनों आरोपी मिलकर प्लॉट पर कब्जा कर अवैध रूप से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे।लसूड़िया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

इंदौर में बुजुर्ग के प्लॉट पर झोपड़ी बनाकर ब्लैकमेलिंग, 2 आरोपी पर केस

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में जमीन कब्जाने और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। दो युवकों ने बुजुर्ग के प्लॉट पर कब्जा कर झोपड़ी बना ली और कब्जा हटाने के बदले 6 लाख रुपए मांगने लगे। पुलिस के मुताबिक 72 वर्षीय गोकुलप्रसाद रायकवार के महालक्ष्मीनगर स्थित प्लॉट (एमआर-3/289) पर आरोपियों ने अवैध कब्जा कर लिया।आरोपी ललित कुमार बेलिया (निपानिया) और राजकुमार मनावत (खरगोन) ने वहां झोपड़ी बनाकर कब्जा जमा लिया।

संपादकीय

नोएडा हिंसा: गंभीर चेतावनी

उत्तर प्रदेश के नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को जिस तरह से हिंसा की गई, वह विकास की उजली तस्वीर के राजनीतिक दावों का अंधेरा पहलू है। यूपी में फैक्ट्रियों में काम के नाम पर कामगारों का कितना जबर्दस्त शोषण हो रहा है, यह घटना उस हकीकत का प्रमाण है। हालांकि राज्य की योगी सरकार ने इस घटना के बाद चेतते हुए न्यूनतम मजदूरी 3 हजार रू. तक बढ़ा दी है। साथ ही इस औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों पर अमल भी शुरू कर दिया है। उधर पुलिस ने हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के मामलो में सात एफआईआर दर्ज की हैं और करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि नोएडा में हिंसा बाहरी लोगों ने फैलाई। दरअसल नोएडा के होजियरी कॉम्लेक्स की फैक्ट्रियों में कार्यरत करीब 42 हजार कर्मचारी ज्यादा वेतन और सुविधाओं को लेकर चार दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इस क्षेत्र में सौ से अधिक कंपनियां हैं। बताया जाता है कि इन फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की उनकी अधिकांश मांगों को लेकर कर्मचारियों, फैक्ट्री मालिकों और सरकार के बीच सहमति बन भी गई थी, लेकिन सोमवार को इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। पुलिस के मुताबिक सोमवार को 80 से ज़्यादा जगहों पर करीब 40 से 45 हजार मज़दूर इकट्ठा हुए थे। इससे ज़िले के कुछ हिस्सों में यातायात बाधित हुआ और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा हुईं। नोएडा के सेक्टर-63 और मदरसन कंपनी परिसर के पास स्थिति बिगड़ी। भड़के कर्मचारियों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को फूंक दिया, तोड़फोड़ और आगजनी की। कर्मचारी मुख्य रूप से ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करने, हर माह की दस तारीख तक एकमुश्त वेतन देने, हर श्रमिक को सैलरी स्लिप अनिवार्य रूप से देने तथा बिना उचित कारण के कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालने आदि की मांग कर रहे हैं। इस बीच योगी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल ही में उभरे श्रमिक असंतोष के बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर श्रमिकों को तत्काल राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नए आदेश एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे। शासनादेश के अनुसार, यह वृद्धि अलग-अलग श्रेणियों में की गई है। अधिकतम करीब 3000 तक का इजाफा हुआ है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि यह तात्कालिक राहत है। आगे श्रम कानूनों के तहत व्यापक समीक्षा के साथ वेज बोर्ड के माध्यम से स्थायी समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नोएडा की हिंसा इस बात का अलार्म है कि हमारे उद्योग जगत के भीतर क्या चल रहा है। दरसअल देश मे श्रमिक आंदोलन लगभग मृतप्राय: होने के बाद मजदूरों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और संघर्ष करने का कोई माध्यम नहीं बचा है। ठेका पद्धति ने श्रमिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। ऐसे में श्रमिकों की नाराजी इस तरह फूटती है। योगी सरकार ने त्वरित निर्णय लेकर संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन लिए गए फैसलों पर ठोस अमल की मॉनिटरिंग भी जरूरी है। वरना नोएडा से शुरू हुई चिंगारी धीरे-धीरे देश में आग की तरह फैल सकती है। जिससे निपटना सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा।

बंगाल चुनाव से पहले 33 फीसदी महिला आरक्षण दांव

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से करीब एक सप्ताह पूर्व 16 से 18 तक तीन दिनों का विशेष लोकसभा सत्र बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को लगातार सदन में उपस्थित रहने और संसद की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, यह विशेष संसद सत्र महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। सरकार का लक्ष्य इस ऐतिहासिक विधेयक पर व्यापक बहस और आगे की प्रक्रिया को तेज करना है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। नई आरक्षण व्यवस्था के साथ लोकसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यह कदम महज एक कानूनी संशोधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी राजनीतिक रणनीति है, जिसमें एक साथ सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और चुनावी लाभ तीनों का समागम है। लोकसभा सत्र बुलाए जाते ही विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। अभी से महिला आरक्षण में दलितों-पिछड़ों के लिये भी अलग कोटा की मांग उठने लगी है।

उधर, बात बीजेपी सरकार की की जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही महिलाओं को अपनी सरकार के केंद्र में रखा है। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण इसी कड़ी की नई इकाई है। महिलाओं के हित में मोदी सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों की बात की जाये तो उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिससे धुएं से मुक्त रसोई और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके साथ ही 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को मजबूती मिली और 100 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध हुई। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (2015), सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा ऋण, जन धन खाते और पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम पर संपत्ति ये सब मिलकर एक ऐसा ताना-बाना बुनते हैं, जिसमें देश की आधी आबादी को सीधे तौर पर सरकारी लाभ की अनुभूति होती है। इन योजनाओं का सीधा असर मतपेटी पर भी पड़ा। जो महिलाएं पहले घर से बाहर निकलकर वोट देने में हिचकिचाती थीं, वे आज एक सक्रिय मतदाता वर्ग बन चुकी हैं। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं ने खुलकर मोदी के पक्ष में वोटिंग की, जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक की नजर से नहीं छूटी।

अब मोदी सरकार इस संबंध को और गहरा करने की दिशा में अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जो लम्बे समय से प्रस्तावित था। बजट सत्र में पेश होने वाले इस विधेयक पर विपक्षी दलों से बातचीत तेज हो गई है। असल में यह मामला इतना सीधा नहीं है। महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र में पास हुआ था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटें दी जाएंगी। लेकिन इसे लागू करने के लिए पहले नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन जरूरी था। यानी 2023 में पास होने के बावजूद यह कानून कागज पर ही रहा। अब सरकार उस शर्त को बदलने की तैयारी में है। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के साथ ही संविधान संशोधन लाने की भी तैयारी कर रही है। यह संविधान संशोधन इसलिए लाया जाएगा, जिससे साल 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटें बढ़ाई जा सकें और 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। साल 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है और इसमें महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।

बहरहाल, बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, बल्कि लोकसभा की संरचना को ही बदल देने की है। 543 से 816 सीटें यह संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इन बिलों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, इसलिए सरकार एनडीए के साथ-साथ विपक्षी दलों जैसे सपा, आरजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से भी समर्थन मांग रही है। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार) जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। शुरुआत में गृहमंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है और कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के साथ बातचीत अभी बाकी है। कांग्रेस के लिए यह बिल एक नैतिक दुविधा की स्थिति है। एक तरफ वह महिला आरक्षण की समर्थक रही है और राहुल गांधी ने खुद इसे जल्द लागू करने की मांग की थी। दूसरी तरफ इस बिल का खुलकर समर्थन करना मोदी को एक ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि का श्रेय देना होगा। हालांकि संकेतों से साफ है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को महिला आरक्षण लागू करने की पहल का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन असली बेचैनी उन दलों में है जो जातिगत समीकरणों पर टिके हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। यह बयान देखने में संतुलित लगता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बहुत गहरी है। समाजवादी पार्टी, राजद तथा द्रमुक जैसे दलों की ओर से महिलाओं के लिए आरक्षण कोटे में ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के लिए अलग से कोटे की मांग उठाई जा सकती है। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटा शामिल करने की मांग उठाई है, जिससे सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। यह मांग तकनीकी रूप से जटिल है, क्योंकि ओबीसी के लिए संसद में आरक्षण का अभी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की असली चिंता कहीं और है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में उनकी राजनीति का आधार पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों का वोट बैंक है। यदि महिला आरक्षण 2029 से लागू हो जाता है और लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती हैं, तो रोटेशन प्रणाली के तहत इन दलों के कई वर्तमान सांसदों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके परिवारों और गुटों के कई दबंग नेताओं के लिए 2029 में चुनाव लड़ना असंभव हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण की मांग दरअसल बिल को उलझाए रखने की एक रणनीति भी हो सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक जो 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनके कोटे के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। फिलहाल ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का जिक्र इस प्रस्ताव में नहीं है। यह वही बिंदु है, जहां टकराव होना तय है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत अभी भी काफी पीछे है। नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, बांग्लादेश की संसद में 50 सीटें और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या मात्र 74 है, यानी करीब 13.6 प्रतिशत। इस लिहाज से 33 प्रतिशत का लक्ष्य एक बड़ी छलांग होगी। मोदी सरकार का यह दांव कई मायनों में अभूतपूर्व है। एक तरफ यह महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है, जहां वह न तो खुलकर समर्थन कर सकता है और न ही पूरी तरह विरोध। महिला मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम कोई भी दल उठाने को तैयार नहीं है। यही मोदी सरकार की रणनीतिक सफलता है उसने विपक्ष को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है, जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है।

बीमा व्यवसाय

डॉ. सुधीर कुमार

कुरुक्षेत्र विवि में सहायक प्रोफेसर

परंपरा और पूंजी से बदलता भारतीय बीमा

कहा जाता है कि विधाता की लिखनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आधुनिक युग में उस 'अनहोनी' के बाद की आर्थिक तबाही को टालने का नाम 'बीमा' है। भारतीय समाज में सदियों से एक धारणा रही है कि 'जो होना है, सो होगा'। इसी प्रारब्ध के भरोसे हमने जोखिमों को गले लगाया। कभी बीमा को 'मृत्यु के भय' का सौदा माना जाता था, जहाँ लोग अपनी मौत पर दांव लगाने से कतराते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ यह 'जीवन के भरोसे' की नींव बन चुका है। आज जब हम 2026 के पायदान पर खड़े हैं, तो भारतीय बीमा क्षेत्र एक ऐसे ऐतिहासिक चौराहे पर है जहाँ परंपरा और आधुनिक पूंजी का मिलन हो रहा है।

भारत में बीमा का इतिहास आर्थिक संप्रभुता और जन-कल्याण की सोच का प्रतिबिंब है। 1956 और 1972 के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता के पैसे को सुरक्षित रखना था, लेकिन 1999 में मल्होत्रा समिति के सुझावों और 'इरडा' के गठन ने उदारीकरण के द्वार खोल दिए। 26 प्रतिशत से शुरू हुआ विदेशी निवेश का सफर आज 2026 में 100 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक पूंजी से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर आमंत्रित करता है। वर्तमान में भारत में बीमा की पैठ जीडीपी का महज 4 प्रतिशत है, जिसका मुख्य कारण पूंजी की कमी रही है। 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से अब विदेशी कंपनियां न केवल 'डॉलर' लाएंगी, बल्कि 'एक्चुअरियल साइंस' की वह विशेषज्ञता भी साथ लाएंगी जो जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे भविष्य के जोखिमों का सटीक आकलन करने में सक्षम है।

हालांकि, यहाँ 'वित्तीय सुरक्षा' का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। जब विदेशी कंपनियों के पास शत-प्रतिशत मालिकाना हक होगा, तब भारतीय विनियामक की भूमिका एक सख्त अभिभावक की तरह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि 140 करोड़ लोगों का यह विशाल 'बाजार' केवल मुनाफे का केंद्र न बनकर एक सुरक्षित 'इकोसिस्टम' में तब्दील हो, जहाँ भारतीय ग्राहकों का पैसा सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रहे। अगर यूपीआई ने भारत के लेन-देन के तरीके को बदला है, तो 'बीमा सुगम' बीमा के वितरण का चेहरा बदलने की कूवत रखता है। यह केवल एक वेब पोर्टल नहीं है, बल्कि यह भारत का 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' है। दशकों से भारतीय बीमा क्षेत्र 'मिस-सेलिंग' के दाग झेलता रहा है। गली-मोहल्ले के एजेंटों द्वारा लुभावने वादे करना, बीमारियों को छिपाने की सलाह देना और फिर क्लेम के समय पॉलिसी के पीछे बारीक अक्षरों में लिखी 'शर्तें' दिखाकर मुकर जाना - यह एक आम कहानी रही है।

'बीमा सुगम' इस एजेंट राज को चुनौती देता है। यह एक ऐसी एकल खिड़की है जहाँ ग्राहक सीधे कंपनी से जुड़ता है। यहाँ तकनीक कानून के साथ कदमताल करती है। जब हर दस्तावेज डिजिटल होगा और रिकॉर्ड 'अपरिवर्तनीय' होगा, तो कंपनियों के लिए क्लेम से मुकर पाना नामुमकिन हो जाएगा। किसी भी कानून की असली परीक्षा कोर्ट रूम के ठंडे कमरों में होती है। बीमा कानूनों में धारा 45 (इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज़) का संशोधन एक क्रांतिकारी कदम है। यह प्रावधान एक तरह से उपभोक्ता का सुरक्षा कवच है। यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने तीन साल तक ईमानदारी से प्रीमियम भरा है, तो कंपनी बाद में यह कहकर क्लेम नहीं रोक सकती कि 'पॉलिसी लेते समय कोई जानकारी छिपाई गई थी'। यह 'उत्तरोत्तर शुचिता' का सिद्धांत है।

न्यायालयों ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'लखमी चंद बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस' जैसे ऐतिहासिक फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बीमा अनुबंध 'पवित्र' हैं। अदालत ने माना कि बीमा कंपनी और एक आम नागरिक के बीच शक्ति का असंतुलन होता है। कंपनी के पास वकीलों की फौज और असीमित संसाधन होते हैं, जबकि नागरिक अकेला होता है। इसलिए, कानून का झुकाव हमेशा कमजोर पक्ष की ओर होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए इस 'संवैधानिक नैतिकता' को समझना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि भारत में 'प्रॉफिट' से ऊपर 'पब्लिक पॉलिसी' और 'सोशल जस्टिस' है।

2025-26 के सुधारों में 'कम्पोजिट लाइसेंस' की अवधारणा एक मास्टरस्ट्रोक है। अभी तक भारत में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के लिए अलग-अलग कंपनियां और अलग-अलग लाइसेंस ज़रूरी थे। यह न केवल कंपनियों के लिए खर्चीला था, बल्कि ग्राहकों के लिए भी थकाने वाला था। अब एक ही कंपनी आपको जीवन बीमा भी दे सकेगी, आपकी कार का बीमा भी करेगी और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को भी कवर करेगी।

यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए वरदान साबित होगी। एक किसान को अब तीन अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इससे कंपनियों की 'ऑपरेटिंग कॉस्ट' कम होगी, जिसका सीधा फायदा प्रीमियम की दरों में कमी के रूप में आम आदमी को मिलेगा। यह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' का एक बेहतरीन संगम है।

जहाँ विदेशी पूंजी आती है, वहाँ डाटा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है। बीमा कंपनियों के पास नागरिकों का सबसे संवेदनशील डाटा होता है - उनकी बीमारियाँ, उनकी जीवनशैली, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके परिवार की जानकारी। 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के युग में यह खतरा बना रहता है कि क्या भारतीय नागरिकों का यह संवेदनशील डाटा विदेशी सर्वरों पर सुरक्षित रहेगा? भारत के 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम' को यहाँ बीमा कानूनों के साथ मिलकर काम करना होगा। किसी भी विदेशी निवेश को अनुमति देते समय 'डाटा लोकलाइजेशन' की शर्त को अनिवार्य बनाना चाहिए। सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं होती, आज के दौर में सुरक्षा 'डाटा' की भी होती है। यदि हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है, तो हमारी आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। विदेशी पूंजी का आगमन कोई डरावना सपना नहीं है, बशर्ते हमारे कानून की तलवार धारदार रहे और रेगुलेटर की आँखें चौकन्नी। बीमा महज़ एक वित्तीय व्यापार नहीं है; यह समाज के प्रति एक 'सामाजिक अनुबंध' है। जब एक पिता अपनी गाढ़ी कमाई से प्रीमियम भरता है, तो वह केवल एक कागज नहीं खरीदता, वह अपने बच्चों का भविष्य और अपनी पत्नी की मुस्कान सुरक्षित करता है।

विदेशी कंपनियों को केवल मुनाफा नहीं, बल्कि 'विश्वास' का व्यापार करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि भारत में व्यापार करने का अर्थ है भारत की विविधता और यहाँ की चुनौतियों को स्वीकार करना। उन्हें अपनी पॉलिसियों को केवल अंग्रेजी बोलने वाले शहरी वर्ग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें उन भाषाओं और उन क्षेत्रों तक पहुँचना चाहिए जहाँ आज भी लोग 'साहूकार' के चंगुल में फंसे हैं। बीमा कानूनों का यह नया युग तभी सार्थक होगा जब गाँव के अंतिम छोर पर बैठा किसान भी अपनी फसल बर्बाद होने पर दर-दर न भटके, बल्कि 'बीमा सुगम' के ज़रिए उसका क्लेम स्वतः उसके खाते में पहुँच जाए। कानून की किताबों से निकलकर जब इंसाफ पीड़ित की चौखट तक पहुँचता है, तभी लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों मज़बूत होते हैं। विधाता की लिखनी को हम भले न बदल सकें, लेकिन उस लिखनी के कारण आने वाली परेशानियों को कम करने का साहस हम 'कानून' और 'करुणा' के मेल से ज़रूर जुटा सकते हैं। पूंजी विदेशी हो सकती है, लेकिन नागरिक भारतीय है। आने वाला समय यह तय करेगा कि हम 'बीमा' के इस नए समंदर में लहरों पर सवार होते हैं या उनमें डूब जाते हैं। उम्मीद है कि भारत का सशक्त विनियामक ढांचा और जागरूक न्यायपालिका मिलकर इस आर्थिक सुरक्षा की नाव को एक सुरक्षित और समृद्ध किनारे तक ले जाएंगे।

ये टी-20 लीग क्या गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बन गई है?

खेल जगत

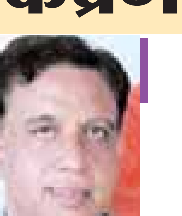

विजय रांगणेकर

(वरिष्ठ खेल समीक्षक)

आईपीएल का रूतबा कई मायनों में अलग हैं। इस खेल में सारी शोहरत बल्लेबाज ले जाता है। क्रीज पर खड़े होकर चारों तरफ शॉट जमाते हुये उसका अंदाज किसी योद्धा जैसा लगता है। कैमरे भी विभिन्न कोणों से उनके शॉट्स को और दर्शनीय बनाते हैं। क्रिकेट के इस फार्मेट में असली आनंद तो चौकों छक्कों का ही रहता है। सब एक तरह से बल्लेबाजी को ही ग्लेमरस बनाते हैं। गेंदबाज अक्सर सहायक भूमिकाएँ निभाते दिखाते हैं। इतने ज्यादा रन बनते हैं कि किसी टीम के लिए 200-250 रन बना लेना भी जीत की गारंटी नहीं रहती।

आधुनिक टी 20 में सुस्ताने की कोई जगह नहीं है। आपको सिर्फ हिट करना होता है और यह ऐसा ही रहेगा। रिकॉर्ड बहुत तेजी से बन और टूट भी रहे हैं। आईपीएल 2023 तक किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर 263 रन था, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। 10 साल तक यह रिकॉर्ड नहीं टूट पाया था, लेकिन आईपीएल 2024 में यह रिकॉर्ड टूट गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक पारी में 287 रन बनाकर क्रिकेट दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इस सीजन में कई खिलाड़ी जिस तेजतर्रार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड भी अधिक दिनो तक टूटने से बचा नहीं रहेगा। 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 15 गेंदों में अर्ध शतक जड़कर सनसनी मचा दी है। उन्होंने यह करिश्मा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ किया और अपने ही रिकॉर्ड को बराबर किया। संजू सैमसन ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ सबसे तेज शतक नाबाद115 नॉटआउट रनों की पारी खेली, जो इस सीजन का अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है। शुरुआती 3 ओवर्स में 58 रन बनाने का कमाल भी अभी देखा गया है। अब तक की बल्लेबाजी निडर इरादों और बहुत तेज गति से रन बनाने यानि पावर हिटिंग की शैली पर आधारित रही है। इस सीजन में बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट काफी ऊंचा रहा है, और युवा भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल की कमान संभाली है।

अब वह पुराना दौर ख़त्म हो चुका है जब टीमें एक या दो स्टार बल्लेबाजों पर निर्भर रहती थीं।अब तो बल्लेबाजों की कता रहै जो नंबर 9 तक गेंदबाजों की पिटाई करने के लिए तत्पर रहती है । बल्लेबाजी के अनेक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। रिकॉर्ड्स बनने और टूटने की प्रकिया में ये लीग गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बन गई है। रनों के मामले में बल्लेबाज और टीमों के हिस्से में जहां शानदार और यादगार रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. वहीं गेंदबाजों के हिस्से में घटिया रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जिसे वे कभी याद नहीं रखना चाहेंगे।. आलम यह है कि बड़ा से बड़ा गेंदबाज गेंदबाजी करने से कतरा रहा है। क्रिकेट के लिए ये शुभ संकेत नहीं है।

क्रिकेट का खेल बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों का भी है। जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं वे गेंदबाजों के विरुद्ध ही होते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, ओवर रेट में कम होने पर 30 गज के बाहर कम फील्डर रखने का रूल, बैटिंग पिच जैसी कुछ चीजे गेंदबाजों के खिलाफ हैं। इन नियमों का फायदा उठाकर बल्लेबाज तो हीरो बन जाता है। लेकिन गेंदबाज को लोग विलेन मानने लगते हैं। सच्चाई ये है कि गेंदबाज नियमों से बंधा हुआ है। उसके पास खुद को बचाने के ज्यादा विकल्प नहीं हैं। कुछ नियम ऐसे भी होने चाहिए जो गेंदबाजों को फेवरकरे। इससे हर मैच में गेंदबाजों पर होने वाला अत्याचार रुक सकता है और क्रिकेट का रोमांच बना रहेगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

रमेशचंद्र शर्मा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हानि-लाभ,जीवन-मरण,जस-अपजस विधि हाथ

दुनिया में जो भी घटित होता है वह अपने पीछे कुछ ना कुछ सवाल जरूर छोड़ जाता है। मसलन जो हुआ उसके होने से किसको कितनी हानि हुई,किसको कितना लाभ हुआ,।उस दौरान कितनों ने जनम लिया,कितने मरे। किसको यश की प्राप्ति हुए और कौन का मुंह काला हुआ अर्थात् अपयश किसकी झोली में आया। अब जैसे हम हानि का विचार करें तो हानि को बढ़ा कर बताना है अथवा घटा कर बताना है यह हालात तय करते हैं। शत्रु को हानि पहुंचने का मामला हो तो हर पक्ष यह बताता है कि हमने सामने वाले के इतने मार दिए। मगर यही हानि जब नफे से जुड़ जाती तो इसे बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है। खासकर तब जब उसका संबंध मुआवजे से जुड़ जाता है। लाभ का मामला ज़रा अलग हट कर होता है।संबंधित दोनों पक्ष यह बताते हैं कि उन्हें लाभ ही लाभ हुआ है। जब कि वास्तविकता यह होती है कि दो की लड़ाई में कभी तीसरे का भी फायदा हो जाता है।जिन पक्षों को लाभ होता है वे परम हंस की मुद्रा अपना लेते हैं। वे एहसास ही नहीं होने देते है कि उनको कितना लाभ हुआ है।वे कितना भी हजम कर जाएं मगर यह सतर्कता जरूर बरतते हैं कि उन्हें भूल से भी डकार नहीं आ जाए। क्योंकि डकार उनके लाभ का बहीखाता खोल कर रख देती है।

घटित घटना में सबसे अहम बात जो होती है वह है यश और अपयश। जाहिर है हर पक्ष यश का दावेदार होता है। जो भी घटना घटी अर्थात युद्ध जैसी,चुनाव जैसी जो भी उठापटक हुई उसमें वहीं विजेता रहा। मजे की बात यह कि जीतने वाला तो जीत के यश का सेहरा अपने माथे पर बांधता ही है हारने वाला भी दावा करता है कि मै ही जीता हूं। तथ्यों के आधार पर जीत का दावा कमजोर पड़ने लगता है तो वह कहता है अनैतिक साधनों से भले ही उसने जीत हासिल कर ली हो मगर नैतिक रूप से विजय हमारी ही हुई है। जब कि हकीकत यह है कि जब जीत ही सर्वोपरि हो जाती है तब नैतिकता तेल लेने चली जाती है। हाल ही में हमने तेल के लिए हुए हालिया युद्ध में यह सब देखा। फिर भी यह बात पक्की मानिए कि कुछ चेहरों पर अपजस की कालिमा इतनी गहराई से पुत जाती है कि वे लाख कोशिशों के बाद भी इस कालिमा को नहीं धो सकते हैं। क्योंकि उनके काले चेहरे की तरफ उंगली उठाने वालों में गैरों के अलावा अपने भी होते हैं। जब अपने ही पराए हो जाते हैं तो उसे तो भगवान भी नहीं बचा पाते हैं।

जब युद्ध होता है तो उसी क्षण उसका विराम भी तय हो जाता है। यही है कि हर जंग का नतीजा युद्ध विराम ही होता है। लिहाजा जो गारंटेड यश की कामना करते है वे युद्ध विराम में अपनी इबारत बड़े इत्मीनान से लिखते हैं।बाज वक्त तो वे बड़े - बड़े संधिबाजों को भी पीछे छोड़ देते हैं। वह भी तब जब उनका अपना दहशतगर्दी का काला इतिहास होता है। पीछे वे इसलिए छोड़ देते है क्योंकि कई जल्दबाज़ तेल और तेल की धार देखने के बजाय यह मान लेते हैं कि तेल की यह जंग आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर ही लेगी। लिहाजा वे आव देखते है ना ताव देखते है पहली फुर्सत में ही वे कहीं ना कहीं कोर्निश बजा आते हैं। उनका यह कोर्निश बजाना ही उनके भावी यश का बैंड बजा देती है।

दरअसल हम तुलसीदासजी के इस कथन, 'हानि - लाभ,जीवन - मरण,जस - अपजस विधि हाथ', संदर्भ में नतीजा निकाले तो किसी को खुश होने या किसी को मलाल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है। यह विधि ही है जो पहले से ही तय कर देती है कि किसको कितनी हानि कितना लाभ होगा। किसके कितने मरेंगे और किसको कितना यश और कितना अपयश मिलेगा। लिहाजा आप तो चचा गालिब को याद करते हुए 'मुंह ढंक कर सोइए, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए,आराम बड़ी चीज है मुंह ढंक के सोइए।'

विचार

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

गांधी है तो भारत है,किताब के लेखक

डॉ. अंबेडकर के मुकाबले इतना कमतर क्यों है दलित आदिवासी नेतृत्व

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि केवल समान अधिकार देने से वास्तविक समानता स्थापित नहीं होगी,जब तक कि इन वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिले। इसलिए आरक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि दलित और आदिवासी समुदाय के लोग विधायिकाओं में पहुंचकर अपने हितों की रक्षा कर सके और अपनी समस्याओं को सीधे सरकार के सामने रख सके। डॉ. अंबेडकर ने राजनीतिक शक्ति को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। उनका विश्वास था कि जब ये वर्ग सत्ता संरचना का हिस्सा बनेंगे,तभी सामाजिक भेदभाव कम होगा और समानता स्थापित होगी। संवैधानिक अधिकारों के बूते सुरक्षित सीटों से जीतकर कई नेता दलित आदिवासियों का संसद में प्रतिनिधित्व करते है। जिस दौर में डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए वंचित वर्गोंका प्रतिनिधित्व किया था, उस समय न तो कोई संविधान था और न ही कोई आरक्षण।

बिहार, यूपी, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दलित और आदिवासी वोट बैंक निर्णायक है। इन राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा से आरक्षित सीटों के माध्यम से कई नेता सामनेआते है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों औरआदिवासियों को संसद तथा विधानसभाओं में आरक्षण इसलिए प्रदान किया क्योंकि ये समुदाय सदियों से सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित रहे थे। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और सत्ता से व्यवस्थित रूप से दूर रखा गया,जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते थे। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि केवल समान अधिकार देने से वास्तविक समानता स्थापित नहीं होगी,जब तक कि इन वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिले। इसलिए आरक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि दलित और आदिवासी समुदाय के लोग विधायिकाओं में पहुंचकर अपने हितों की रक्षा कर सके और अपनी समस्याओं को सीधे सरकार के सामने रख सके। डॉ. अंबेडकर ने राजनीतिक शक्ति को सामाजिक परिवर्तन का साधनमाना। उनका विश्वास था कि जब ये वर्ग सत्ता संरचना का हिस्सा बनेंगे,तभी सामाजिक भेदभाव कम होगा और समानता स्थापित होगी। संविधानिक अधिकारों के बूते सुरक्षित सीटों से जीतकर कई नेता दलित आदिवासियों का संसद में प्रतिनिधित्व करते है। जिस दौर में डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था, उस समय न तो कोई संविधान था और न ही कोई आरक्षण।अब वंचित वर्गों के लिए कई संवैधानिक अधिकार है लेकिन इतने वर्षों के बाद भी बाबा साहेब अंबेडकर के मुकाबले कोई दलित या आदिवासी नेता दूर दूर तक नजर नहीं आता और यहीं कारण है की देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या अच्छी खासी होने के बाद भी एक भी ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जिस पर यह समुदाय भरोसा कर सके। रामविलास पासवान एक दलित नेता थे,जिनकी पहचान जमीनी राजनीति और सामाजिक-न्याय के मजबूत नेता के रूप में रही। अब उनके बेटे चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे है। बिहार में दलितों का अच्छा खासा वोट है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव और सामाजिक दूरी देखने को मिलती है। शिक्षा और जागरूकता बढ़ने से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अस्पृश्यता के रूप बदलकर अभी भी मौजूद हैं। दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रहती हैं। अधिकांश दलित समुदाय भूमिहीन या सीमांत किसान हैं। मजदूरी,असंगठित क्षेत्र और प्रवासी श्रम पर निर्भरता अधिक है। सरकारी योजनाओं के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। चिराग पासवान,दलित आइकॉन की पारंपरिक छवि से बाहर निकलकर खुद को एक बड़े,युवा और सर्वसमावेशी नेता के रूप में पेश कर रहे है,जो कानून-व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे भी उठाते है लेकिन उन्होंने कोई ऐसा दलित आंदोलन खड़ा नहीं किया जिससे वे भारत के दलित आदिवासियों के विश्वसनीय चेहरा बन सके। रामदास अठावले भारतीय राजनीति में एक प्रमुख दलित नेता है। वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष है,जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित पार्टी है। अठावले महाराष्ट्र से आते है। उनकी राजनीति का मुख्य आधार दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और आरक्षण का समर्थन रहा है। वेअपने अलग और कभी-कभी हास्यपूर्ण बयानों के लिएचर्चा में रहते है,जो कई बार गंभीर राजनीति के अनुरूप नहीं माने जाते।

रामदास अठावले की राजनीति विचारधारा और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है, जो उन्हें सत्ता में तो रखती है लेकिन वे विश्वसनीय दलित नेतृत्व की तलाश में कहीं दिखाई नहीं देते। भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए अलग अलगजातियों और धर्मों को अलग अलग प्रकार से उभारा जाता रहा है। यहां राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में सबसे पहले सत्ता,उसके बाद व्यक्तिगत हित, फिर समाज और अंत में कहीं राष्ट्र नजर आता है। भारत की राजनीतिक पार्टियां देश के लोकतंत्र को अगड़े पिछड़ों में देखती है और दलित आदिवासी नेता भी उन्हीं राजनीतिक दलों के वोट पाने के संसाधन बन गये है। मायावती डॉ. अंबेडकर के समावेशी समाज की कल्पना को साकार करने कि बात कहती रही है जबकि उसके राजनीतिक क्रियाकलाप ठीक इसके उलट नजरआते है। बसपा जातीय समस्या की समाप्ति से ज्यादा जातीय उभार देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है। दूसरी और व्यक्ति-केंद्रित नीतियों ने दलित राजनीति की दीर्घकालिक मजबूती को कमजोर किया है और उसमे मायावती की भूमिका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। बहुजन समाज पार्टी में निर्णय लेने की शक्ति अत्यधिक एक व्यक्ति तक सीमित हो गई। इससे जमीनी नेतृत्व और नए दलित नेताओं का उभरना बाधित हुआ। परिणामस्वरूप,दलित आंदोलन की विचारधारात्मक ऊर्जा और संगठनात्मक विस्तारकमजोर पड़ गया। कांशीराम के समय जो बहुजन आधारित व्यापक सामाजिक गठबंधन था,वह धीरे-धीरे सिमटकर चुनावी रणनीति तक सीमित हो गया। इससेदलित राजनीति का व्यापक सामाजिक आधार कमजोर हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेनकी छवि एक ओर आदिवासी अधिकारों के सशक्त नेता की रही लेकिन वे कई विवादों से भी घिरे रहे। उन पर सामाजिक न्याय से ज्यादा भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप लगे,जिससे आदिवासी आंदोलन की नैतिक शक्ति कमजोर हुई। वे झारखंड सेन तो गरीबी खत्म कर पाएं और न ही आदिवासियों के पलायन को रोक पाएं। जगजीवनराम की पुत्री मीरा कुमार को ही लीजिये। 2009 से 2014 तक वे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। बिहार से वे कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रही। उन्होंने बिहार में दलितों के लिए आंदोलनया बड़े सामाजिक कार्यक्रम खड़े नहीं किए, जिससे शिक्षा,भूमि और रोजगार जैसे मुद्दों पर ठोस बदलाव नहीं दिखा। उनके उच्च पद का सीधा और ठोस प्रभाव बिहार के दलितों की जमीनी स्थिति पर कोई बदलाव नहीं ला सका। दरअसल दलित-आदिवासी राजनीति ने भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव किए है। डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान नेसमानता, स्वतंत्रता और आरक्षण जैसे अधिकार सुनिश्चित किए, जिससे इन समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पहचान मिली। संसद, विधानसभाओं और प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी और मायावती,शिबू सोरेनतथा मीरा कुमार जैसे नेता सत्ता के उच्च पदों तक पहुँचे। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है,जिसने आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान को मजबूती दी। किन्तु, यह भी एक सच्चाई है कि समानताऔर सम्मान की वास्तविक स्थिति अभी अधूरी है। ग्रामीण भारत में आज भी जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। दलितों के लिए भूमिस्वामित्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थायी रोजगार अभी भी सीमित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति और जटिल है,जहां विकास परियोजनाओं, खनन और वन नीतियों के कारण विस्थापन और आजीविका का संकट बना रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक अधिकारों का लाभ जमीनी स्तर तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। डॉ.भीमराव अंबेडकर का नेतृत्व परिवर्तनकारी था,जबकि आज का नेतृत्व अधिक व्यावहारिक और सत्ता-केंद्रित हो गया है। उनका नेतृत्व मूलतः सामाजिक क्रांति और वैचारिक संघर्ष पर आधारित था। अंबेडकर का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन और समानता स्थापित करना था। उन्होंने शिक्षा,संगठन और आंदोलन के माध्यम से दलित समाज को जागरूक किया। संविधान में मौलिक अधिकार,आरक्षण और सामाजिक न्याय के प्रावधान उनके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का परिणाम हैं। अंबेडकर का नेतृत्व समाज की संरचना बदलने वाला था जबकि आज का नेतृत्व व्यावहारिक और सत्ता-केंद्रित हो गया है। देश की दलित-आदिवासी राजनीति धीरे-धीरे सत्ता-केंद्रित और चुनावी रणनीतियों तक सीमित होती गई है। बाबा साहेब कहते थे की केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, दलित आदिवासी और पिछड़ों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में जमीनी बदलाव आना चाहिए। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,कौशल विकास, भूमि सुधार और सामाजिक जागरूकता पर विशेष देने की जरूरत है। डॉ. अंबेडकर की प्राथमिकता सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने की थी,वे राजनीतिक सत्ता से प्रेम नहीं करते थे बल्कि उसका उपयोग करके सामाजिक न्याय की स्थिति मजबूत करना चाहते थे। अब दलित आदिवासी नेता सत्ता में बने रहना चाहते है,वे चुनाव जीतने को सर्वोत्तम लक्ष्य समझते है। जाहिर है जहां सत्ता लोलुपता हो, वहां अंबेडकर नहीं हो सकते। यही कारण है की बाबा साहेब के बाद कोई भी ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जिसे देश में व्यापक स्वीकार्यता और वंचित वर्ग का विश्वास हासिल हो।

दृष्टिकोण

स्मिता कुमारी

लेखिका सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की निदेशक हैं।

अम्बेडकर हम सबके, हम सब अम्बेडकर के

बाबा साहेब अम्बेडकर कभी सोचे नहीं होंगे कि कुछ लोग उनके नाम पर एक अलग ब्राह्मणवाद फैला देंगे। ब्राह्मणवाद का सम्बन्ध किसी विशेष जाति से नहीं बल्कि एक खास विचारधारा से है जो निराधार श्रेष्टता के बदौलत वंचित समुदाय पर शासन करना सीखता है। अब ठीक वैसे ही कुछ लोग अम्बेडकरवाद के नाम पर यह जताना शुरू कर दिए हैं कि अम्बेडकरवाद से सम्बंधित व्यक्ति दलित समुदाय से होगा और अम्बेडकर के नाम पर वे पूजा-पाठ करने के साथ एक विशेष जाति के खिलाफ नफरत फैसला भी शुरू कर दिए हैं।

वास्तव में अम्बेडकर किसी जाति विशेष से खुद को मुक्त कर अपने आप को सबके लिए बना गए। अम्बेडकर से बेहतर भला इस बात को कौन समझेगा कि ब्राह्मणवाद का जहर किस तरह उनके जीवन के उत्थान में रोड़ा रहा और उसी के साथ कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने ही उनकी योग्यता पर भरोसा जता उनको शिक्षा दिलाने से कानून मंत्री बनने तक में साथ खड़े रहे, सहयोग किए। बौद्ध धर्म को अम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास को तोड़ने तथा सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए अपनाया। मगर इसके लिए वह जिस धर्म को ग्रहण किए उस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी राजकुमार सिद्धार्थ थे। यह तथ्य इस बात का प्रणाम है कि अम्बेडकर ने आडम्बर का त्याग किया लेकिन जाति के आधार पर किसी मनुष्य का नहीं। वर्तमान में कई बार अम्बेडकर पर लिखते या बौद्ध धर्म पर बात करते यह महसूस हुआ कि लोगों ने अम्बेडकर की तरह पढ़ना तो दूर अम्बेडकर को भी नहीं पढ़ा और यह मान बैठे हैं कि जाति के आधार पर अम्बेडकर केवल दलित जाति के प्रतिनिधि थे या बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित ही होते हैं।

हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा क्या आप अम्बेडकर को मानती है? क्या अम्बेडकरवादी हैं, यानि दलित हैं? मैंने कहा अंबेडकर को मानने वाले सभी अम्बेडकरवादी नहीं होते हैं। मैं बाबा साहेब अंबेडकर को उनके कार्य के लिए दिल से सम्मान करती हूँ। रही बात शूद्र या दलित या वंचित समुदाय से होने की, तो महिला होने से बड़ा वंचित समुदाय का कोई और नहीं होता, फिर चाहे वह महिला किसी भी जाति की हो। हाँ यह सच है कि जाति के आधार पर शोषण और बढ़ जाती है। आगे बात होते हुए बौद्ध धर्म पर चर्चा हुई तब उन्होंने फिर से पूछा बौद्ध धर्म तो दलित जाति अपनाते हैं। मैंने कहा मैं जहाँ तक पढ़ी हूँ महात्मा बुद्ध 'बुद्ध' बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ थे यानि सवर्ण जाति के। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना जातिगत भेद यानि ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए किया था ना कि किसी विशेष जाति के लिए। तो इस अर्थ में बौद्ध धर्म के समर्थक अम्बेडकर भी हो सकते हैं और सम्राट अशोक भी या किसी भी जाति, लिंग के लोग हो सकते हैं। बुद्ध को मानने या अंबेडकर को मानने के लिए एक विशेष जाति में होना जरूरी नहीं है।

अम्बेडकर ने कभी भी एक विशेष जाति के लिए कोई उत्थान का कार्य नहीं किया बल्कि एक विशेष विचारधारा के लोगों के शोषण से सबको मुक्त करने का काम किया। 1920 में मूकनायक का प्रकाशन दलितों के आवाज के रूप में भले ही किया गया हो मगर उसका उद्देश्य यह भेदभाव बरकरार रखने के लिए नहीं बल्कि भेदभाव मिटाकर समानता स्थापित करने के लिए था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह इसलिए नहीं किया गया कि तालाब के पानी पर अधिकार किसी एक जाति के लोग से छीनकर दूसरे को दे दिया जाए बल्कि यह सत्याग्रह इसलिए किया गया था ताकि पानी पर सबका समान अधिकार हो। 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर सत्याग्रह करने वाले अंबेडकर 1935 में बौद्ध धर्म इसलिए अपना लेते हैं ताकि बौद्ध धर्म में कोई ब्राह्मणवाद जैसा आडंबर नहीं था और यह सभी मनुष्य को बराबरी का अधिकार देता है, बौद्ध धर्म में किसी भी मनुष्य से जाति और लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाता है, यह हिंसा, अंधविश्वास और अवतार जैसे अवधारणाओं के खिलाफ है। 1932 में पुन एक्ट या 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना इसलिए किया गया ताकि दलित, श्रमिक और गरीब समुदाय को बराबरी तक पहुंचा जा सके। इसका अर्थ है कि वह किसी एक समुदाय की हित के लिए काम नहीं कर रहे थे बल्कि वह सभी को बराबरी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। 1947 से 1951 तक कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के हित के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विवाह और तलाक के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। मगर यह केवल दलित महिलाओं के लिए नहीं किया गया था बल्कि यह सभी समुदाय की महिलाओं को बराबरी तक पहुंचाने के लिए किया गया कार्य था। अक्टूबर 1956 में अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षाभूमि में बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, आडंबर और छुआछूत के खिलाफ अपनाया था। लेकिन उन्हें मानने वाले आज उनको एक जाति विशेष के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद द्वारा खींची गई शोषण की सीमा रेखा को तोड़कर एक लंबी लकीर खींचकर वंचित समुदाय को दिया और अपनी शिक्षा के आधार पर यह स्थापित किया कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल किसी विशेष जाति को नहीं है बल्कि शिक्षा प्राप्ति योग्यता के अनुसार हर इंसान का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके समाज में समानता स्थापित करने के लिए कार्य किया और देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें देश के सभी नागरिकों को सामान के अधिकार देने की जिक्र की गई। आज उनके जितना शिक्षित व्यक्ति देश-विदेश में मिलना मुश्किल है। उनके पथ पर चलने की बजाय कुछ लोग उनकी मूर्ति को पूजा पाठ करके उनके द्वारा विरोध की गई विचारधारा को ही दूसरे रूप में स्थापित कर रहे हैं। अंबेडकर को मानने का अर्थ यह नहीं कि उनकी पूजा की जाए, यह भी नहीं कि अंबेडकर को एक विशेष जाति में बांधकर देखा जाए, बल्कि अंबेडकर ने जिस जाति बंधन से खुद को मुक्त किया उन्हें उसी तरह देखा जाए। उनके तरह शिक्षित होने का कार्य और पूरे समाज के उत्थान करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए तब ही यह कहा जा सकता है कि हम अंबेडकर के वंशज है। अंबेडकर ने सबको अपनाया और सबके लिए काम किया। ब्राह्मणवाद जब किसी मंदिर और देवता पर अपना एकल अधिकार बताता है तो एक दूसरे समुदाय को उससे अपना कहने से वंचित करता है, अम्बेडकर इसके ही तो खिलाफ गए फिर अम्बेडकर को किसी एक के विशेषधिकार से देखना भी तो ब्राह्मणवाद है। जब अम्बेडकर ने खुद इस विचार को बहिष्कार करके खुद को सबके लिए समर्पित किया तो अंबेडकर को किसी एक जाति के नजर से देखना वैसा ही होगा जैसे ब्राह्मणवाद का विचारधारा। अंबेडकर सभी के थे, अम्बेडकर सभी के हैं और हम सब अंबेडकर के हैं इस बात को आत्मसात करके ही सब अम्बेडकर को अपना कह सकते हैं।

सिनेमा

डॉ. मनीष जैसल

लेखक मीडिया प्रोफेसर हैं।

अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम को डॉ. अम्बेडकर कितना याद हैं ?

भारतीय सिनेमा के परिदृश्य में भीमराव रामजी आंबेडकर की उपस्थिति जितनी व्यापक और केंद्रीय होनी चाहिए थी, वह आज तक दिखाई नहीं देती। यह केवल एक सांस्कृतिक विचारों की कमी नहीं, बल्कि हमारे समय की वैचारिक प्राथमिकताओं का दर्पण भी है। जो संभवतः धुंधला भी है। जिस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की बुनियादी आत्मा को गढ़ा, जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को सामाजिक संघर्ष के केंद्र में रखा, उसके विचारों को लोकप्रिय संस्कृति, विशेषकर सिनेमा ने बहुत देर से और सीमित रूप में अपनाया है। जबकि विडंबना यह है कि सार्वजनिक मंचों पर संविधान और उसके अनुच्छेदों का बार-बार उल्लेख होता है, पर उस संविधान के पीछे की वैचारिक चेतना को समझने की कोशिश उतनी गंभीरता से नहीं होती दिखाई देती। सिनेमा, जो जनचेतना को आकार देने का एक प्रभावी माध्यम रहा है, इस दूरी को कम कर सकता था, लेकिन उसने इस जिम्मेदारी को लंबे समय तक टाल दिया।

दरअसल, आंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं, बल्कि भारतीय समाज की संरचनात्मक असमानताओं के खिलाफ एक निरंतर प्रतिरोध की कहानी है। 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्मे आंबेडकर ने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना किया। लेकिन उन्होंने इस अनुभव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे ज्ञान और संघर्ष की ताकत में बदला। बॉम्बे विश्वविद्यालय से लेकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक की उनकी शैक्षिक यात्रा इस बात का प्रमाण है कि वे शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार मानते थे। उनकी प्रसिद्ध थीसिस 'द प्रॉब्लम ऑफ रूपीस' आज भी आर्थिक नीतियों में संदर्भित होती है, जो यह दर्शाती है कि वे केवल सामाजिक विचारक ही नहीं, बल्कि गहरे आर्थिक विश्लेषक भी थे। लेकिन भारतीय सिनेमा ने इस बौद्धिक गहराई को बहुत कम जगह दी; उसने संघर्ष को तो दिखाया, पर उस संघर्ष की वैचारिक नींव को अक्सर सतही स्तर पर ही छोड़ दिया।

डॉ अंबेडकर पर प्रत्यक्ष रूप से फिल्में बनने से पहले भारतीय सिनेमा में जाति का प्रश्न पूरी तरह अनुपस्थित नहीं था, लेकिन उसका स्वरूप बहुत सीमित और सुधारवादी था।

निर्देशक फ्रांज ओस्टेन की अछूत कन्या जैसी फिल्में सहानुभूति जगाती हैं, पर वे उस सामाजिक ढांचे को चुनौती नहीं देतीं, जो असमानता को जन्म देता है। यहाँ समस्या को व्यक्तिगत स्तर पर हल करने की कोशिश होती है, जबकि आंबेडकर इसे एक गहरी संरचनात्मक समस्या के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि शुरुआती फिल्मों में दलित पात्र अक्सर करुणा के पात्र बनकर रह जाते हैं—वे परिवर्तन के प्रहरी नहीं बन पाते। यह प्रस्तुति उस सामाजिक मानसिकता का विस्तार है, जो असमानता को स्वीकार तो करती है, पर उसे बदलने की वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रखती।

सत्तर और अस्सी के दशक में समानांतर सिनेमा ने इस दृष्टिकोण को चुनौती देने की कोशिश की। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकारों ने समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की कहानियों को गंभीरता से उठाया। आक्रोश और अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में व्यवस्था की क्रूरता, न्याय की विफलता और सत्ता की हिंसा को तीखे ढंग से प्रस्तुत किया गया। लेकिन यहाँ भी आंबेडकर का वैचारिक ढांचा प्रत्यक्ष रूप से अनुपस्थित रहता है। यह सिनेमा समस्या को पहचानता है, पर समाधान की दिशा में स्पष्ट वैचारिक मार्गदर्शन नहीं देता। अंबेडकर का चिंतन, जो शिक्षा, संगठन और संघर्ष के जरिए सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, इन फिल्मों में प्रत्यक्ष रूप से जगह नहीं बना पाता।

मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में तो स्थिति और भी जटिल रही। यहाँ जाति का प्रश्न अक्सर 'कमर्शियल टूल' की भेंट चढ़ गया, या फिर उसे इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह व्यापक सामाजिक आलोचना में तब्दील न हो सके। दलित पात्रों को या तो हास्य के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया, या फिर उन्हें सहानुभूति के पात्र के रूप में सीमित कर दिया गया। यह दृष्टिकोण अंबेडकर के उस विचार के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें वे स्वाभिमान, अधिकार को केंद्र में रखते हैं। सिनेमा का यह रवैया दरअसल उस सामाजिक मानसिकता का विस्तार है, जो असमानता को स्वीकार तो करती है, लेकिन उसे बदलने की वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रखती।

1990 के दशक के बाद भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और पहचान के सवालों के उभार ने सिनेमा को भी प्रभावित किया। इसी दौर में फ़िल्म निर्देशक जब्बार पटेल की फ़िल्म डॉ बाबासाहेब अंबेडकर सामने आती है। यह फिल्म अंबेडकर के जीवन का सबसे व्यापक और शोधपरक सिनेमाई रूपांतरण मानी जाती है। इसमें उनके बचपन के अनुभव, विदेशों में शिक्षा, राजनीतिक संघर्ष, गांधी के साथ वैचारिक मतभेद और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से दिखाया गया है। यह फिल्म इस बात का प्रमाण है कि जब सिनेमा गंभीरता से अंबेडकर को समझने की कोशिश करता है, तो वह एक गहरे और प्रभावशाली दस्तावेज का रूप ले सकता है।

इसके समानांतर मराठी सिनेमा ने आंबेडकर के जीवन को लगातार अपने केंद्र में रखा। 'भीम गर्जना', 'बालक आंबेडकर', 'रामाबाई भीमराव आंबेडकर' और 'बाल भीमराव' जैसी फिल्मों ने उनके जीवन के विभिन्न चरणों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया।

'रामाबाई भीमराव आंबेडकर' विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह आंबेडकर के जीवन को उनकी पत्नी के नजरिए से देखती है, जिससे उनके व्यक्तित्व का एक मानवीय और संवेदनशील पक्ष सामने आता है। शरण कुमार कबूर की कन्नड़ फिल्म "Dr. B. R. Ambedkar" (2005) ने भी उनके जीवन को व्यापक भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

इन कई फिल्मों के साथ-साथ डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन माध्यमों ने भी इस विमर्श को विस्तार दिया है। कई शैक्षणिक और सरकारी फिल्मों ने संविधान निर्माण, सामाजिक आंदोलनों और आंबेडकर के विचारों को केंद्र में रखा। हाल के वर्षों में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में उनके विचारों को समकालीन संदर्भों में पुनर्पाठ करने की कोशिश करती हैं—जहाँ समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्न आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

लेकिन दुनियाँ में सबसे ज़्यादा सिनेमा बनाने वाली इस इंडस्ट्री के लिए ये फ़िल्में ऊँट के मुँह में जीरा हैं।

यात्रा की शुरुआत हुई है लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। कई बार सिनेमा में आंबेडकर की छवि केवल प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देती है—दीवारों पर लगी तस्वीरों या संवादों के जरिए—लेकिन उनके विचारों की गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया जाता। यह एक प्रकार की सतही स्वीकृति है, जो वास्तविक वैचारिक प्रतिबद्धता का विकल्प नहीं हो सकती।

अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान है, जिसे वे केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के स्पष्ट प्रावधान हैं जिनमें छुआछूत और मैला ढोने की प्रथा पर रोक, समान वेतन, श्रम के अधिकार, मतदान का अधिकार और कानून के समक्ष समानता प्रमुख हैं। लेकिन उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वालों की नीयत सही नहीं होगी, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, और सिनेमा के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण।

हाल के वर्षों में फैंड्री और सैराट जैसी फिल्मों ने जाति के प्रश्न को नए तरीके से प्रस्तुत किया है। इन फिल्मों में आंबेडकर का नाम भले ही सीधे तौर पर न लिया गया हो, लेकिन उनके विचार स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। तमिल सिनेमा में पा. रंजीत ने इस विचारधारा को लोकप्रिय संस्कृति में स्थापित करने का काम किया है।

महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी पहलें इस बात का प्रमाण हैं कि डॉ अंबेडकर केवल विचारक नहीं, बल्कि सक्रिय आंदोलनकारी भी थे। उन्होंने कहा था—'हम जो अधिकार मांग रहे हैं, वह कोई भीख नहीं, बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' यह विचार सिनेमा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिनेमा केवल कहानियाँ नहीं सुनाता, बल्कि समाज की चेतना को भी आकार देता है।

आंबेडकर और सिनेमा का संबंध केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का प्रश्न है। सिनेमा को यह तय करना होगा कि वह केवल मनोरंजन का माध्यम बना रहेगा या समाज के सबसे कठिन सवालों से संवाद करने का साहस भी करेगा। डॉ अंबेडकर का जीवन और विचार इस संवाद की सबसे सशक्त शुरुआत हो सकते हैं। यदि सिनेमा इस दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ता है, तो वह न केवल अंबेडकर को सही अर्थों में सम्मान देगा, बल्कि भारतीय समाज को भी एक नई दृष्टि प्रदान करेगा, एक ऐसी दृष्टि, जिसमें समानता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन सके।

इस देश की जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे तो कुछेक प्रतिशत लोग ही किसी फ़िल्म को हिट करा देते हैं, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व वाली फ़िल्में एक दस्तावेज की तरह सदियों तक सहेज कर रखी जाती है। भारत में सिनेमा अपनी जिस आज़ादी के कारण आज दर्शकों तक संदेश के रूप में पहुँच रहा है उसका एक श्रेय डॉ अंबेडकर को जाता है। अब वो समय आ गया है कि सिनेमा इंडस्ट्री के लोग स्वतंत्रता को नागरिक अधिकार का दर्जा दिलाने वाले डॉ. अम्बेडकर के लिए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। उनके विचारों का सिनेमा बनाकर।

सोहागपुर पुलिस की सफलता

करीबन एक किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त

सोहागपुर। पुलिस मुख्यालय के प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के निर्देश के उपरांत पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साईकृष्णा एस. थोटा (आईपीएस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री अभिषेक राजन (रा. पु.से.) नर्मदापुरम के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री संजू चौहान (रा. पु.से.) के मार्गदर्शन में सोहागपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की पतारसी की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 13 अप्रैल.26

को विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई।कि समीपवर्ती ग्राम टूराखापा में जीतू पारदी अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय करने अवैध लाभ अर्जित कर रहा हैं। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने तत्काल सोहागपुर पुलिस की टीम को ग्राम टूराखापा में रवाना की। इस पुलिस टीम उपनिरीक्षक राहुल पटेल आदि ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ।मुखविर की सूचना के स्थान पर दबिश देकर जीतू उर्फ जीतेन्द्र (पिपिन्डे) पारदी पिता सागर (पिपिन्डे) पारदी उम्र 32 साल निवासी ग्राम टूराखापा को पकड़ा। पुलिस ने उसके कब्जे से 960 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। जिसकी कीमत लगभग 14 हजार 400 रूपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजा जप्त करके आरोपी के विरूद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया ।

उल्लेखनीय भूमिका- इस मामले में उल्लेखनीय भूमिका नगर निरीक्षक राहुल रायकवार, उपनिरीक्षक राहुल पटेल, मुकेश सोनी, प्रधान आरक्षक शैलेन्द वर्मा ,महिला आरक्षक नेहा रघुवंशी, आरक्षक विवेक सोनपुरे, सुनील ओझा, मनोहर दायमा, चालक आरक्षक गोपाल चौधरी आदि की रही।

माखन नगर में भारत रत्न संविधान रचियता की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई

सोहागपुर। विख्यात कवि दादा माखनलाल चतुर्वेदी की नगरी माखन नगर में भारत रत्न संविधान रचयिता डॉ भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर माखन नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के अलावा अहिरवार समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सर्वश्री हेमंत यादव, रत्नेश बडगूजर, संजय गिल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमृत बिंदु दरिया, पूर्व पार्षद द्वारका प्रसाद

चौधरी, हकीम खान, संजय अहिरवार ,बाबू खान, सुबोध दुबे, प्रकाश चौरसिया स्वदेश मालवीय, सेलू दुबे,जितेन चौधरी मुकेश अहिरवार, जाहिद खान, बंटी चाचा,विशाल जैन,लीलाधर यादव, रामकिशन यादव, राजेश चौहान, इरफान बाबा, शेखर राजपूत, संजेश गोलियां अनिल चौरे मुकेश चौहानबलराम अहिरवार महेश अहिरवार तेजराम चौधरी राजू अहिरवार प्रकाश अहिरवार तनु अहिरवार मनीष अहिरवार हेमंत अहिरवार, बबलू अंसारी देवीराम अहिरवार ,बद्रीप्रसाद अहिरवार, रेवती अहिरवार, वकील ऋतुराज पटेल सेदरवाड़ा राज अहिरवार, डमरू अहिरवार राजेश अहिरवार आदि उपस्थित थे।इस अवसर पर की वक्ताओं ने भारत रत्न संविधान रचियता डाक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर सारगर्भित उद्बोधन दिए। तथा उनके बताए मार्गों एवं सिद्धांतों पर चलने का आवाहन किया।

बाबासाहेब के विचारों से प्रेरित होकर देश निरंतर प्रगति कर रहा है : विधायक

बाबासाहेब अंबेडकर जयंती पर जेएच कॉलेज बैतूल में कार्यक्रम आयोजित

बैतूल। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में जे.एच. कॉलेज बैतूल के सभागार में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा बाबासाहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार, नगर पालिका अध्यक्ष सारणी किशोर वर्दे सहित हंसराज धुर्वे, अनिल कापसे, सुरेश गायकवाड, डॉ महेंद्र सिंह चौहान, शशिकांत नागले, श्री टेकाम, दशरथ धुर्वे, कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग विवेक पांडे तथा अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाबासाहेब के विचारों, उनके योगदान एवं सामाजिक समरसता पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की छात्रा लक्ष्मी प्रधान ने डॉ. अंबेडकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉ. योगेश पंडाग्रे ने अपने संबोधन में कहा कि बाबासाहेब का योगदान केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने श्रमिकों के कार्य समय को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को शिक्षा एवं मतदान का अधिकार, तथा सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने औद्योगिक विकास, बैंकिंग प्रणाली

और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक भारत की नींव रखीं। उन्होंने बाबासाहेब से जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कहा कि बाबासाहेब का जीवन संघर्ष, संकल्प और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और कोलंबिया जैसे संस्थान में अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। उन्होंने विश्व के सबसे अच्छे संविधान का निर्माण किया जिसके बल आज हम सभी सामाजिक समरसता, समानता, बंधुत्व और एकता की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी से बाबासाहेब के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार ने बाबासाहेब के संविधान निर्माण और सामाजिक समरसता में योगदान को याद करते हुए उनके पदचिह्नों पर चलने का संदेश दिया। अनिल कापसे ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हर समस्या का समाधान संभव है और बाबासाहेब ने समाज को यही दिशा दी। सहायक आयुक्त विवेक पांडे ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, आवास सहायता, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही स्वरोजगार योजनाएं एवं अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हितलाभ वितरण एवं सम्मान

कार्यक्रम में विभिन्न हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत रमेश हुरमाड़े को 90 हजार एवं गुलाबराव खातरकर को 89 हजार रुपये, वहीं संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत सुनील मंदरे को 9 लाख एवं अतुल वानखेड़े को 1 लाख 52 हजार रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं–नीलम, टीना ऊईके, रेणुका धुर्वे, विद्या एवं निशा वाडिया–को सम्मानित किया गया।

शादी का प्रलोभन देकर दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। शादी का प्रलोभन देकर दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तरप्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी फेसबुक के माध्यम से नोएडा निवासी सुनील राजपूत (उम्र 25 वर्ष) से पहचान हुई थी। परिचय के बाद आरोपी बैतूल आया और सोनी होटल में कमरा लेकर महिला से मिला, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3-4 बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके पश्चात आरोपी के कहने पर महिला बिना परिजनों को बताए नोएडा पहुंची, जहां आरोपी ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। ठगी और मानसिक आघात से पीड़ित महिला वापस बैतूल आकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली से एक विशेष पुलिस टीम नोएडा रवाना की गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर बैतूल लाया। आरोपी को विधिवत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस कार्रवाही में निरीक्षक देवकरण डहेरिया, उप निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, उप निरीक्षक चित्रा कुमरे, आरक्षक नितिन चौहान, आरक्षक अनिरुद्ध यादव, आरक्षक राजेन्द्र धाड़से, आरक्षक दीपेन्द्र की सराहनीय भूमिका रही।

विधायक के प्रयासों से लादी से भाडावाड़ी मार्ग निर्माण में तकनीकी बाधा हुई समाप्त

आमला। आमला-सारणी विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के समन्वय एवं प्रयासों से विधानसभा के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य लादी एवं भाडावाड़ी वासियों के लिए सुरिक्षत सम्पर्क करने के उद्देश्य से निर्मित होने वाले लादी से भाडावाड़ी सडक़ निर्माण में तकनीकी अड़चनें दूर हो गई है। जल्द ही 439 लाख रुपए वाली स्वीकृत सडक़ का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। गौरतलब है कि वन क्षेत्र से जाने वाली प्रस्तावित सडक़ के निर्माण में विभिन्न तकनीकी अड़चनो के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था। विधायक डॉ. पंडाग्रे के द्वारा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से उक्त सडक़ निर्माण में सभी बाधाएं दूर हो चुकी है। विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे के प्रयासों से स्वीकृत लादी भाडावाड़ी सडक़, आमला सारणी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जन जातीय बाहुल्य ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों के

लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है गौरतलब है कि लगभग एक पखवाड़ा पहले क्षेत्रीय विधायक डॉ. पंडाग्रे ने दूरस्थ वन ग्राम लादी प्रवास के दौरान ग्रामीणों को उक्त सडक़ निर्माण हेतु सभी विभागीय रुकावटों को दूर कर सडक़ निर्माण के लिए आश्वस्त किया था। उसी तारतम्य में विधायक डॉ. पंडाग्रे के द्वारा विभागीय समन्वय एवं प्रयासों से तकनीकी अड़चनो के दूर होने के साथ उक्त सडक़ निर्माण जल्द प्रारंभ होगा। भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों ने विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे का आभार व्यक्त किया।

बी.आर.ए. अंबेडकर कॉलेज में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित

बैतूल। भीमराव रामराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय बैतूल में उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के आदेशानुसार सोमवार 13 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम का लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में देश भर से आई महिलाओं हेतु नारी शक्ति वंदन

कार्यक्रम को संबोधित किया गया। यह कार्यक्रम 2 चरणो में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक होंगे। जिसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम को लागू करवाना है। बी.आर.ए. अंबेडकर कॉलेज के विशाल सभागार में लाइव प्रोग्राम में महाविद्यालय के संचालक इंजीनियर ध्रुवप्रकाश अग्रवाल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जी.डी. देशमुख सहित समस्त स्टाफ एवं बी.एड. स्कालर्स उपस्थित थे।

फायर सेवा के लिए वैकल्पिक नंबर जारी

101 और कंट्रोल रूम न लगने पर इन नंबरों पर करें कॉल

बैतूल। नगर पालिका परिषद बैतूल ने अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक संपर्क नंबर जारी किए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडेय के अनुसार, फायर वाहन उपलब्ध कराने हेतु सामान्यतः 101 तथा पुलिस कंट्रोल रूम बैतूल के मोबाइल नंबर 7049101017 पर संपर्क किया जाता है, लेकिन इन नंबरों पर संपर्क न होने की स्थिति में नागरिक सीधे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। जारी सूची के अनुसार कार्यालय अधीक्षक विजय हुद्दार 8770748518, स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनेलिया 6260913576, फायर वाहन चालक सुनील भलावी 9406049503, रत्नेश पाल 9424007748, शितलेश पवार 8085236236, विशाल खरे 9993537200, शरद यादव 8966097721 तथा नवनीत महरणवार 9424005115 के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।

हेमंत खंडेलवाल ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा की

ब्राह्मण समाज ने सामुदायिक भवन एवं वाटिका की रखी मांग

बैतूल। बैतूल सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा काफी अरसे से परशुराम सामुदायिक भवन निर्माण एवं परशुराम वाटिका निर्माण की मांग की जा रही थी। इस मांग को समाज द्वारा मंगलवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल के समक्ष रखा। जिस पर श्री खंडेलवाल ने जिले के

ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम सामुदायिक भवन के प्रथम चरण निर्माण एवं वाटिका निर्माण के लिए सनातन ब्राह्मण समाज को 20 लाख देने की घोषणा की है। इस अवसर पर सनातन ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल मिश्र उपाध्यक्ष राजेश अवस्थी, अनिल दुबे, एस.पाटिल, श्रीमती साक्षी शर्मा, संगीता अवस्थी, आरती अवस्थी नीलम दुबे, मीनाक्षी शुक्ला, श्रीमती पाटिल आदि स्वजातीय बंधु मौजूद थे। समस्त ब्राह्मण समाज ने हेमंत खंडेलवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

छोटा महावीर जी कागदीपुरा तीर्थ में पंचकल्याण में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य मिले, तीर्थ कमेटी ने विनती की

धार। जयपुर में विराजित आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को छोटा महावीर जी कागदीपुरा तीर्थ कमेटी द्वारा छोटा महावीरजी में पंचकल्याण में गुरुदेव का सानिध्य मिले श्रीफल अर्पित किया । गुरुदेव ने अपने वात्सल्यमयी आशीर्वाद में तीर्थ के सरंक्षण और विकास की बात कही।आपने बताया छोटा महावीरजी के महावीर स्वामी अतिशयकारी है ।आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होगी ।आपने पंचकल्याणक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

समय आगे तय होगा। संघ में करीब 32 मुनिराज और आर्यिका माताजी है ।

प्रतिनिधि मंडल में तीर्थ प्रमुख विनय छाबड़ा ,इंजी. आशीष जैन, अजीत जैन - दिगम्बर जैन समाज अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल, सचिव संजय छाबड़ा, अजय लुहाड़िया, मोसम झांझरी, अशोक कासलीवाल, संजय लुहाड़िया, मुकेश गांगवाल नितिन गंगवाल, संजय सेठी मांडू, पुष्पेन्द्र गंगवाल नालछा ,यश छाबड़ा, पवन पहाड़िया, प्रवीण गोधा धार , दिलीप लुहाड़िया इंदौर उपस्थित थे।

भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकरजी की जयंती पर भाजपा नेताओं ने उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की

धार। बाबा साहेब भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री एवं धार सांसद सावित्री ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती, धार विधानसभा क्षेत्र विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा,अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनमचंद फकीरा, अभियान जिला टोली जिला संयोजक विपिन राठौर, सह संयोजक अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश चौहान ने त्रिमुर्ति चौराहे स्थित बाबा साहेब प्रतिमा पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की।

श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, समानता एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हुए संविधान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनके विचार, संघर्ष और आदर्श आज भी हमें एक समतामूलक एवं

सशक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।

निलेश भारती ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के पुरोधा, 'भारत रत्न' श्रद्धेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन करता हूँ। शिक्षा और समानता के माध्यम से आपने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को गति दी। समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित सशक्त भारत की जो नींव आपने रखी, वह आज भी राष्ट्र निर्माण का पथ प्रशस्त कर रही है।

विधायक नीना वर्मा ने गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में 'अभिव्यक्ति स्थल' को 'बाबा साहब अंबेडकर उद्यान सह अभिव्यक्ति स्थल' के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विशाल निगम और जयराज देवड़ा भाजपा नेता अशोक जैन ,विश्वास पांडे, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी, जिला उपाध्यक्ष राखी राय ,अनिल जैन बाबा ,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा , कालीचरण सोनवानीया ,मोहित तातेड, रतन पवार ,सुरेश प्रजापत ,राजेश हारोड़ ,टोनी ठाकुर ,मनीष प्रधान , महेश बोडाने, बादल मालवीय देवेंद्र रावल ,सोनिया राठौर ,अतुल फकीरा ,निशा शर्मा ,अल्पना जोशी, अनुसूया वैष्णव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर त्रिमुर्ति चौराहे स्थित बाबा साहेब प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक तथा परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई और प्रतिमा स्थल को दीपमाला से सजाया गया। संचालन पुरुषोत्तम चौहान ने किया। आभार राकेश चौहान ने माना।

बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर को अपनाएं और बिजली बिल में बचत की शुरुआत करें

स्मार्ट मीटर से दिन में बिजली जलाना 20: तक सस्ता

हरदा,(निप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को आधुनिक और पारदर्शी बिजली सेवाओं से जोड़ने के लिए ष्स्मार्ट मीटरिंगष् अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। कंपनी ने न केवल तकनीक में सुधार किया है, बल्कि उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए श्टाइम ऑफ डेश् टैरिफ के तहत सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है। यह छूट इस अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड / अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र में उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट मीटर की स्थापना का कार्य तीव्रता से जारी है। भोपाल जिले में अब तक 4 लाख 84 हजार से अधिक परिसरों में स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के 16 जिलों यथा अशोकनगर, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, ग्वालियर, दतिया, गुना, हरदा, मुरैना, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, श्योपुर, शिवपुरी एवं विदिशा जिले में अब तक 9 लाख 18 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। आरडीएसएस योजना के तहत पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में 26 लाख 79 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने है और आगामी महीनों में स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य में और तेजी लाई जाएगी।

कंपनी की अपील: बनें स्मार्ट उपभोक्ता

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए आने वाली तकनीकी टीम का सहयोग करें। स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिलिंग संबंधी शिकायतों और गलत रीडिंग की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है। स्मार्ट मीटर न केवल सटीक रीडिंग सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करते हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की सीधी छूट दी जा रही है। इससे वाशिंग मशीन, इंडक्शन चूल्हा या अन्य भारी उपकरणों का उपयोग दिन में करना अब काफी किफायती हो रहा है। उपभोक्ता कंपनी के मोबाइल ऐप उपाय के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की बिजली खपत को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण संभव है। स्मार्ट मीटर के संबंध में किसी भी जानकारी अथवा समस्या के निराकरण हेतु कॉल सेन्टर 1912 अथवा नोडल अधिकारी श्री कैलाश कुमार चौधरी, प्रबंधक(स्मार्ट मीटरिंग सेल) से ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले की 271347 लाडली बहनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की 40 करोड़ रूपए की राशि

विदिशा,(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सीहोर जिले के आष्टा से 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना के तहत 35वीं किस्त के रूप में1,836 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से विदिशा जिले की 271347 महिलाओ के बैंक खातों में 40 करोड रुपये की राशि अंतरित की गई है। विदिशा के एनआईसी व्हीसी कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी, विदिशा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और लाडली बहनाएं मौजूद रहीं। इस दौरान उपस्थित सभी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के लाइव उद्बोधन को देखा, सुना गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसबा ने विदिशा जिले की लाभान्वित लाडली बहनों की जनपद व निकायवार जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान जनपद पंचायत बासौदा की 40483, ग्यारसपुर की 24300, कुरवाई की 27310, लटेरी की 25552, नटेरन की 33161, सिरोंज की 36584, विदिशा की 29327, नगरपालिका गंजबासौदा की 11948 ,सिरोंज की 8746, विदिशा की 25579, नगर परिषद कुरवाई की 2990, लटेरी की 3337 , शमाशाबाद की 2030 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते मे राशि अंतरित की जाएगी। राशि अंतरण के कार्यक्रम का प्रसारण सभी आंगनवाडी केन्द्रों व पंचायत मुख्यालयों पर लाडली बहनों को देखने सुनने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे।

अम्बेडकर जयंती पर आदिवासी बालक छात्रावास में हुआ वृहद श्रमदान

बैतूल,(निप्र)। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में प्रात: 8 बजे आदिवासी बालक छात्रावास परिसर गुरूद्वारा रोड गंज में वृहद श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रावास परिसर में स्थापित डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा के आसपास व्यापक साफ-सफाई की गई। साथ ही परिसर में स्थित जल कुंड के संरक्षण एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से श्रमदान किया। इस स्वच्छता अभियान में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री विवेक पांडे, सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के जिलास्तरीय छात्रावासों के अधीक्षकगण एवं सहायक आयुक्त कार्यालय के समस्त कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित की।

ग्रामीणों ने सुनाई खरी-खोटी, विधायक बोले- विरोध ही कर लो

नर्मदापुरम, (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी के ग्राम मल्काजरा रविवार को पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी और जनता के बीच सीधा टकराव हुआ। रोड, नाली की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक को घेर खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर विधायक भी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा अब आप विरोध ही कर लो। गांव मल्काजरा में विधायक के विरोध के वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आया है। विधायक ठाकुरदास नागवंशी, अपनी पत्नी और भाजपा पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ ग्राम मल्काजरा में गांव चले अभियान के तहत एक रोड का भूमिपूजन करने पहुंचे थे। विधायक के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक ठाकुर दास का विरोध शुरू कर दिया।ग्रामीण पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर नाराज थे। ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध करने पर विधायक ठाकुर दास नाराज हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ने और उंगली दिखाते हुए बोले 'आप लोग विरोध ही करते रहो...' विधायक के इस बयान के बाद मौके पर माहौल और ज्यादा खराब हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याएं लंबे समय से जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। एक ग्रामीण यह भी कहते सुनाई दें रहा कि आपको चार बार वोट देकर जीता रहे, विधायक बना रहे। पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

विधायक की पत्नी और महिलाओं को घेरा

ग्रामीणों ने विधायक की पत्नी और महिला समर्थकों जिस गाड़ी से गए थे। उसे भी ग्रामीणों ने घेर लिया। उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कहा हम रोज क्षेत्र के दौरे पर रह रहे है। रविवार को मल्काजरा गांव हुए थे। जहां रोड का भूमिपूजन किया। कुछ ग्रामीणों के कहना था कि रोड से पहले नाली बनाओ। जबकि रोड के साथ नाली बनेंगी ही।

बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह से जुड़ी सेवाएं देने वालों से अपील

हरदा। जिला प्रशासन हरदा द्वारा आगामी 20 अप्रैल को ''अक्षय तृतीया'' के अवसर पर बड़ी संख्या में होने वाले विवाह समारोहों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से विवाह से संबंधित सभी सेवा प्रदाताओं से विशेष अपील की गई है। जिला हरदा के विवाह से जुड़ी सभी सेवाएं देने वाले पंडित, धर्मगुरु, होटल, केटरर, टेंट हाउस संचालक, बैंड-बाजा वाले, ब्युटी पार्लर, घोड़ी-बग्गी संचालक, मैरिज गार्डन मालिक, छायाकार, स्टूडियो संचालक एवं अन्य आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे विवाह से पूर्व बालक-बालिका की आयु का सत्यापन अवश्य करें।

प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अनुराग दुबे ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे विवाह न केवल कानूनन वर्जित हैं, बल्कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। उन्होने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

मां बेतवा के उदगम स्थल ग्राम झिरी से नदी संरक्षण का संदेश

उद्गम स्थल से प्रवाहित नदियां सदानीरा होती है: श्री नागर

रायसेन,(निप्र)। नदियों को बचाने के लिए उनके उद्गम स्थलों 6जलस्रोतों8 का संरक्षण अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से नदी का शुद्ध जल आगे प्रवाहित होता है। उद्गम स्थल से प्रवाहित नदिया ही सदानीरा होती है। उद्गम स्थल ही नदी के अस्तित्व और मानवीय स्वास्थ्य का आधार होते हैं। अगर इन्हे नहीं बचाया गया तो नदियों के साथ-साथ मानव जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। यह बात आज बेतवा नदी उदगम स्थल ग्राम झिरी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर राज्य मंत्री दर्जा ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा नवांकुर संस्थाओं एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के श्रमदान एवं भव्य नदी संवाद कार्यक्रम में कही। इस दौरान श्री नागर ने कहा कि हम नदी स्थलों को पर्यटन का केन्द्र बनाकर गंदगी कर चले जाते हैं, हमें नदियों को स्वच्छ रखने सामुदायिक प्रयास करने होंगे। मॉ बेत्रवति की धारा को निरंतर बनाएं रखने में स्थानीय लोगों की भूमिका अहम है, जन अभियान परिषद की तरफ से एक अनऔपचारिक समिति का गठन कर हम उदगम स्थल की देखरेख में सहयोग कर सकते हैं। इस दौरान संत नारायण नागर श्री श्री जी आवलीघाट वालों ने नदी के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान, त्रिवेणी पेड़ लगाए गए, मां बेतवा उदगत स्थल का पूजन एवं कलश यात्रा निकाली गई। उदगम स्थल पर श्रमदान कर सफाई की गई। इस दौरान संभाग समन्वयक श्री वरूण आचार्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान पर जानकारी देते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला श्री समन्वयक कल्याण सिंह राजपूत, ब्लाक समन्वयक निशा बहेकार सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

नर्मदापुरम में खेल मंत्री ने मल्टीस्पोर्ट्स टर्फ का किया शुभारंभ

विश्वास सारंग बोले- फिट युवा ही बना सकता है देश को मजबूत

नर्मदापुरम ,(निप्र)। मप्र के सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग रविवार रात को अल्प प्रवास पर नर्मदापुरम पहुंचे। खेल मंत्री ने दादा कुटी पहुंचकर वहां पूजन की। फिर उन्होंने एक अत्याधुनिक खेल परिसर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री सारंग ने हर व्यक्ति के लिए खेल के महत्व को बताया।

उन्होंने कहा मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शिकागो सम्मेलन से लौटकर आने के बाद विवेकानंद जी के पास कुछ युवा पहुंचे और बोले कि हम चाहते है कि आपके जैसे मार्ग पर चले, भगवा पहन संन्यास लेना चाहते है। सनातन का परचम लहराकर देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। विवेकानंद मुस्कुराएं बोले कि भारत देश को बड़ा बनाना चाहते हो तो उसके लिए भगवा धारण, संन्यास लेने की जरूरत नहीं, वो सामने फुटबॉल का मैदान पड़ा है। वहां जाओ, खेलों, अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को ठीक करो। इस देश का नागरिक, युवा शारीरिक, मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा, तभी यह भारत बड़ा देश बनेगा।

खेल मंत्री ने कहा खेल किसी व्यक्ति को समाज के सुव्यवस्थित नागरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक अंग खेल से जुड़े। हिंदुस्तान को हिट करना है तो फिट करना होगा। फिटनेस के दौर में आज हम सभी तेज गति से आगे बढ़े। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। खेल मंत्री ने लोकार्पण के साथ ही बैटिंग भी की। इस दौरान सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक विजयपाल सिंह, आचार्य पंडित सोमेश परसाई, आध्यात्मिक गुरु सांई बल्लभदास, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, पूर्व विधायक सविता दीवान, जनपद अध्यक्ष, भूपेन्द्र चौंकाने सहित अन्य उपस्थित रहे।

नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने किया पदभार ग्रहण

बैतूल,(निप्र)। नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2017 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे को बैतूल जिले के कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के पालन में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया।

जिले में आगमन पर नवागत कलेक्टर डॉ. सोनवणे का अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित अन्य अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। डॉ. सोनवणे इससे पूर्व आयुक्त नगर निगम रीवा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

रोस्टर निर्धारित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की होगी नियमित समीक्षा : नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे से आज कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सौजन्य भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए विभागीय प्रशासनिक संरचना, प्रगतिरत एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभागवार रोस्टर निर्धारित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही, उन्होंने कलेक्टर कार्यालय भवन का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

टोल बचाने रॉन्ग साइड दौड़ रहे ट्रक-डंपर :नर्मदा पुल के पास अचानक कट मारने से हादसे का खतरा

नर्मदापुरम,(निप्र)। औबेदुल्लागंज-बैतूल हाईवे स्थित नर्मदा पुल के पास ट्रक, डंपर चालक 'शॉर्टकट' रास्ता अपना रहे हैं। हाईवे पर अचानक रॉन्ग साइड (नियम विरुद्ध) तरह से गाड़ी निकालने से खुद के साथ लोगों की जान खतरे में डाल रहे। ड्राइवर बुधवाडा टोल प्लाजा पर टोल बचाने के लिए यह शॉर्ट कट रास्ता अपना रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। रॉन्ग साइड से डंपर पार कराने से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है।

नर्मदापुरम से भोपाल जाते समय नर्मदा नदी के पुल से डेढ़ किमी दूर टोल बूथ है। टोल बूथ पर होने के बाद ही भोपाल से बैतूल जाने वाली सड़क पर आया जा सकता है। टोल पार करने से ड्राइवरों को टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ड्राइवर नियम विरुद्ध तरह से सड़क पार कर रहे हैं। अचानक इस तरह सड़क पार करने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए दुर्घटना का जोखिम बना रहता है।

कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर किया गेहूँ की वास्तविक उपज का निरीक्षण

हरदा,(निप्र)। जिले में किसानों को गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन स्लॉट बुक करने में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने ग्राम स्तर पर पहुंचकर किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। उन्होने ग्राम अहलवाडा में जाकर किसानों से सीधे संवाद किया एवं उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने खेतों में खड़ी एवं कटाई उपरांत रखी गई गेहूं की फसल का अवलोकन कर वास्तविक उपज का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को स्लॉट बुकिंग में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होने स्पष्ट किया कि शासन किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

केवल उत्पादन करना काफी नहीं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी : मंत्री पटेल

रायसेन,(निप्र)। रायसेन स्थित दशहरा मैदान में आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव के दूसरे दिन उन्नत कृषि विषय पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इसी क्रम में सेमीनार हॉल-1 में एफपीओ मीट का आयोजन किया गया, जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा सहित विधायकगणों, वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों द्वारा सहभागिता की गई।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि केवल उत्पादन करना ही काफी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी है। एफपीओ कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना छोटे-छोटे किसानों को एक मंच पर लाकर उनकी आय बढ़ाना और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उद्देश्य के साथ की गई। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि पहले किसानों को जो बीज मिलता था, वह कई बार ऊगता ही नहीं था। इसी प्रकार किसी दवाई या कीटनाशक के उपयोग से फसल को ही नुकसान होने या नकली खाद देने की स्थिति में संबंधित पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। बिचौलिए भी किसानों की मेहनत की उपज का सही दाम नही देते थे और स्वयं कई गुना लाभ कमाते है। इन कठिनाईयों से किसानों को बचाने के लिए एफपीओ की स्थापना की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों के बीच भरोसा बढ़ाने और उत्पाद की गांरटी के लिए एफपीओ की स्थापना की गई, जिसमें किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान कर बिचौलियों की श्रृंखला को समाप्त करने पर काम किया गया ताकि फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों को मिल सके। इसके अलावा छोटे किसान जो व्यक्तिगत रूप से बीज, खाद या मशीनरी महंगे में खरीदते हैं, उन्हें एफपीओ के माध्यम से थोक दर पर इनपुट (बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड) कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार किसानों को उत्पाद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग की सुविधा मिली है जिससे कि वह केवल कच्चा माल नहीं बेचते बल्कि वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) के द्वारा अधिक लाभ कमाते हैं। इसके अलावा एफपीओ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी करता है। इस दौरान एफपीओ से जुड़े किसानों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए।

वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई को होगा

हरदा,(निप्र)। नालसा, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में लंबित प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु 9 मई, 2026 को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, हरदा तथा तहसील न्यायालय, टिमरनी और खिरकिया में किया जावेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण , वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत बिल, जलकर, सम्पत्तिकर बिल संबंधी प्रकरण सेवा मामलें, जो सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित है, राजस्व तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। उन्होंने आमजन से नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करने की अपील की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में सेन जयंती पर संत शिरोमणि सेनाचार्य जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की प्रतिमा पर इंदौर में माल्यार्पण किया।

आज एमपी में नारी शक्ति वंदन का शंखनाद

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को मिलेंगी नई ऊंचाइयां : सीएम यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को नई ऊंचाइयां देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' की मूल भावना को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 10 से 25 अप्रैल तक 'नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा' मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 अप्रैल को शाम 4 बजे रवीन्द्र भवन में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा। इस दौरान 'महिला नेतृत्व की यात्रा' विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो महिला शक्ति के गौरवशाली इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाएगी। इस गरिमामयी समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव शामिल होंगे और शासन व्यवस्था में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने और नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने पर विशेष विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को संबोधित भी करेंगे और सरकार के उस संकल्प को दोहराएंगे, जिसके तहत मध्यप्रदेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की आवाज और अधिक मुखर होगी। कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सक्रिय प्रदेश की अग्रणी महिला नेत्रियां शामिल होंगी। समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा बागरी और श्रीमती राधा सिंह सहित प्रतिष्ठित शिक्षाविद सुश्री शोभा पेठणकर की विशेष रूप से उपस्थिति रहेगी।

जमीन से लेकर शिखर तक का प्रतिनिधित्व

समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें पद्मश्री से सम्मानित विभूतियां, महिला चिकित्सक, वकील, कलाकार और इंजीनियर शामिल होंगी। साथ ही, समाज की मुख्यधारा को गति देने वाली लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी, स्व-सहायता समूहों की सदस्य, मैदानी स्तर पर कार्य करने वाली पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी और महिला मीडिया प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनेंगी।

गांव-गांव तक फैलेगी चेतना की लहर

पखवाड़े के दौरान केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में जन-जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हो रही हैं। जिनमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के महत्व पर ग्रामीण महिलाओं के साथ संवाद हुआ। साथ ही प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में 'नारी शक्ति पदयात्रा' और शिक्षण संस्थानों में 'युवा संवाद' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को इस सामाजिक बदलाव से जोड़ा जा रहा है। शासन का मानना है कि महिलाओं की निर्णय क्षमता में वृद्धि होने से न केवल सामाजिक चेतना आएगी, बल्कि जन-विश्वास भी और अधिक गहरा होगा।

मदरसन कंपनी कर्मचारियों और पुलिस के बीच हुई झूमाझटकी

महू-नीमच मार्ग को जाम करने की मजदूरों ने की कोशिश, पुलिस ने हटाया

पीथमपुर (नप्र)। पीथमपुर के औद्योगिक नगर सेक्टर 3 स्थित मदरसन कंपनी की यूनिट 1 के बाहर मंगलवार को करीब 500 महिला और पुरुष कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन उनका आर्थिक शोषण कर रहा है और हक की आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहा है।

कर्मचारी बोले-कंपनी में काम के घंटे तय नहीं

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी में काम के घंटे तय नहीं हैं। प्रबंधन उनसे आठ घंटे से अधिक काम करवाता है, लेकिन वेतन वृद्धि की बात आने पर कोई सुनवाई नहीं होती। एक महिला कर्मचारी रश्मि ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई में कम वेतन पर गुजारा करना मुश्किल है, और प्रबंधन का रवैया मानसिक प्रताड़ना का कारण बन रहा है।

प्रदर्शनकारी बोले-विरोध करने पर कंपनी ने कुछ को नौकरी से निकाला- हड़ताल का मुख्य कारण हाल ही में प्रबंधन की ओर से की गई कार्रवाई बताई जा रही है। मजदूरों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनके कुछ साथियों को बिना किसी ठोस वजह के नौकरी से निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन इस तरह की कार्रवाई से उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक निकाले गए साथियों को वापस काम पर नहीं लिया जाता, वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती और कार्य के घंटे सुनिश्चित नहीं किए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ का खौफ

युवक को बनाया निवाला, जमतरा गेट पर ग्रामीणों का भारी हंगामा

छिंदवाड़ा (नप्र)। जिले के पेंच टाइगर रिजर्व के जमतरा गेट क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक घटना सामने आई। बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत फैल गई, वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने जमतरा गेट पर देर रात तक हंगामा किया। मृतक की पहचान बिछुआ ब्लॉक के नाहरझिर निवासी दिनेश रेवतकर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दिनेश किसी निजी कार्य से टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में गया था। इसी दौरान जंगल में मौजूद बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

देर शाम मिला शव, गांव में मचा मातम- बताया जा रहा है कि दिनेश शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव जंगल क्षेत्र में मिला। शव मिलने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

जमतरा गेट पर जुटे सैकड़ों ग्रामीण- घटना से आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में जमतरा गेट पर पहुंच गए। लोगों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि बफर जोन में लगातार वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ रही है, लेकिन विभाग द्वारा पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।

मुआवजे और सुरक्षा की मांग- ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं। बाघ की गतिविधियों की जानकारी पहले भी विभाग को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज हमारे गांव का एक बेटा चला गया। जब तक विभाग ठोस सुरक्षा इंतजाम और मुआवजे का वादा नहीं करता, आक्रोश शांत नहीं होगा।

वन विभाग पर लापरवाही के आरोप- ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी कई बार बाघ की गतिविधियों की सूचना दी गई थी, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। घटना के बाद अधिकारियों के मौके पर पहुंचने में देरी को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई। घटना के बाद नाहरझिर सहित आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने जंगल की ओर जाना बंद कर दिया है और बच्चों को भी अकेले बाहर नहीं भेजा जा रहा है।

रील बनाते समय ट्रेलर से टकराए बाइकर्स, 3 की मौत

दो की हालत नाजुक ; मौके पर मिला गन लाइटर

मऊगंज (नप्र)। मऊगंज के पन्नी-पथरिया नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक, पल्सर 220 बाइक पर सवार तीन युवक मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे। युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। साथ ही मोबाइल पर रील बना रहे थे। इसी दौरान उनका ध्यान भटक गया और बाइक सीधे सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

एक ही ट्रेलर से टकराई दो बाइक- हैरानी की बात यह है कि इस हादसे के ठीक बाद पीछे आ रही एक अन्य बाइक (टीवीएस अपाचे) भी अनियंत्रित हो गई। अपाचे पर सवार दो युवक भी उसी ट्रेलर से जा भिड़े। इस दूसरे हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

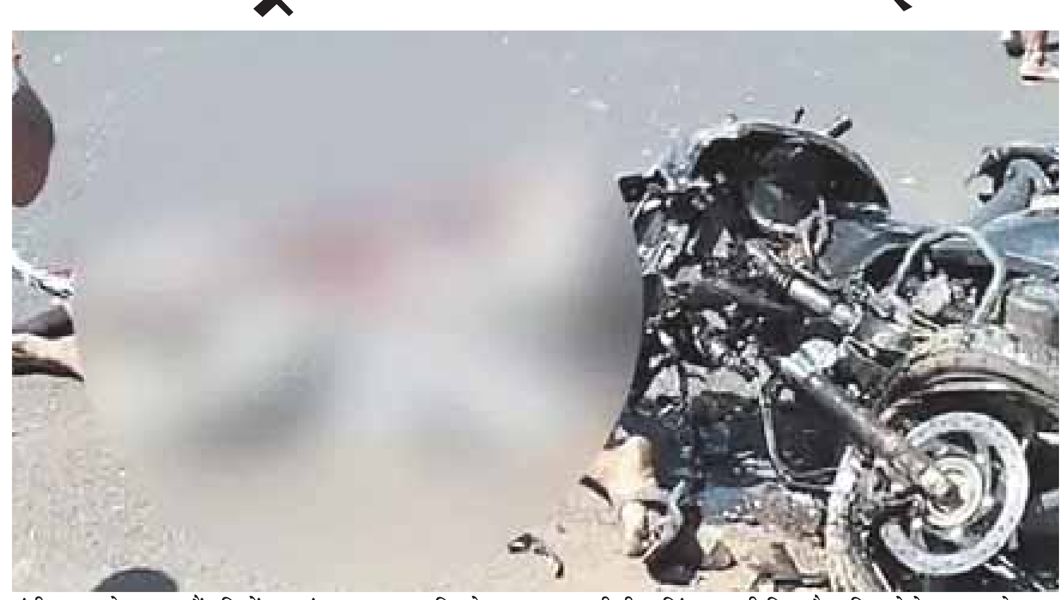

मृतक से गन लाइटर मिला है- सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रीना सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि मृतकों के पास से एक गन लाइटर भी मिला है। पुलिस ने ट्रेलर ट्रक को जब्त कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस पीछे थी...कार पलटी, शहडोल के कुएं में गिरे 3 तस्कर, मौत

शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। इसमें 6 लोग सवार थे। भागने के दौरान इनमें से कुछ कुएं में गिर पड़े।

घटना सोमवार देर रात कामता तिराहे के पास हुई। मंगलवार सुबह पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन लाशें बरामद कर ली हैं। बाकी कार सवारों की तलाश जारी है।

थाना प्रभारी जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि सोमवार रात जैतपुर से कामता की ओर जा रही एक कार डायल 112 में तैनात आरक्षक कृष्णेंद्र यादव और पायलट ड्यूटी पर मौजूद टीम को संदिग्ध लगी। पुलिस को देखते ही कार सवारों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पुलिस ने उनका पीछा शुरू कर दिया। तेज रफ्तार कार कामता कॉलेज तिराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई।

पत्नी के कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमवाया

झाबुआ में महिला के मुंडन का वीडियो, लोग तमाशबीन बने रहे ; 4 आरोपी गिरफ्तार

झाबुआ (नप्र)। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में एक महिला को अमानवीय 'सजा' दी गई। महिला के पति को उसके कंधे पर बैठाकर गांव में घुमवाया गया और उसका मुंडन भी कर दिया गया। वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे।

घटना काकनवानी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 अप्रैल को हुई। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। पुलिस ने पति समेत 5-6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दूसरे के साथ चली जाने का आरोप- दरअसल, महिला पर आरोप था कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई थी। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर महिला को प्रताड़ित किया। उसे जबरन पति को कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया गया।

पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा दी- वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को तलाश कर सुरक्षा दी। एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया के मुताबिक, मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में कुल करीब 10 लोग शामिल थे।

राज्यपाल पटेल ने भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर किया नमन

लोकभवन के बैंक्वेट हॉल में हुआ कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल मंगलवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल श्री पटेल ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।

लोकभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर लोकभवन के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री डॉ. अम्बेडकर को आदरांजलि अर्पित की।

जंगल में भटकता मिला ऑस्ट्रेलियाई युवक

अंधेरे में अकेले देखकर पुलिस हैरान, बैग किसी को छूने नहीं दिया

रतलाम (नप्र)। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले स्थित एक जंगल में ऑस्ट्रेलियाई युवक भटकते हुए मिला है। अंधेरे में भटकते विदेशी युवक को देखकर लोगों ने पुलिस की टीम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जंगल में ऑस्ट्रेलियाई युवक के होने की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

रास्ता भटककर पहुंचा युवक- बताया जा रहा है कि सोमवार की रात बांगरोद जड़वासा रोड एक फॉरेन व्यक्ति रास्ता भटक कर आ गया है, बांगरोद पुलिस चौकी इंचार्ज प्रदीप शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद। फॉरेन व्यक्ति को बांगरोद चौकी पर ले जाया गया। इसके बाद उसके दस्तावेजों की जांच की गई।

युवक ने खुद को ऑस्ट्रेलिया का निवासी बताया- रतलाम पुलिस की टीम युवक को वहां से सुरक्षित नामली थाना लेकर पहुंची। यहां पर युवक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। इसके साथ ही उसके पास से वीजा भी मिला है। हालांकि वह अपना नाम सही तरीके से नहीं बता पाया है।

बैग टच नहीं करने दिया

पुलिस की जांच के दौरान युवक ने अपना बैग टच नहीं करने दिया है। कोई करीब जाने की कोशिश करता तो वह बैग खींच लेता था। ऐसे में पुलिस को अनुमान है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है।

राधे-राधे जपता रहा

वहीं, युवक इस दौरान राधे-राधे जपता रहा है। उसके शरीर पर भगवा कपड़े भी थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह भारत में धार्मिक यात्रा पर आया हुआ था। पुलिस ने दस्तावेजों का सत्यापन किया है। एएसआई प्रदीप शर्मा ने कहा कि युवक के पास दिल्ली का टिकट मिला है। जांच के बाद हमारी टीम ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है कि वह यहां कैसे पहुंचा।

दिल्ली का टिकट मिला

इसके साथ ही युवक के पास से दिल्ली का टिकट मिला है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह रास्ता भटक गया था। पुलिसकर्मियों ने जांच के बाद युवक को रतलाम स्टेशन पर छोड़ दिया है। इसके बाद ट्रेन पकड़कर वह रवाना हो गया है।

शोभायात्रा रूट पर चूने की जगह डाला कीटनाशक पाउडर, लोगों की सांसें हुईं परेशान

मंडीदीप। नगर पालिका मंडीदीप में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि स्वच्छता अधिकारी जावेद खान के निर्देश पर नगर में निकलने वाली शोभायात्रा के रूट मैप को चिन्हित करने के लिए चूने की जगह कीटनाशक पाउडर का छिड़काव कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शोभायात्रा मार्ग पर दुकानों के सामने और मुख्य रास्तों पर डाले गए इस कीटनाशक पाउडर के कारण स्थानीय लोगों और दुकानदारों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने आंखों में जलन और घुटन जैसी शिकायतें भी जताई हैं।

व्यापारियों का कहना है कि जहां चूने का उपयोग किया जाना चाहिए था, वहां जहरीले कीटनाशक का उपयोग करना गंभीर लापरवाही है, जो आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल इस पाउडर को हटाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।